

● वर्ष-6

॥ संगछध्वम् संवदध्वम् ॥

● अंक-32

रायपुर, शुक्रवार
11 सितंबर 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> यात्री किराए के विषय का ...



अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में बोले पीएम मोदी

टकराव नहीं सहयोग से होगा बदलाव

नई दिल्ली। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने भारत का अंतरिक्ष दृष्टिकोण रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीम हैं और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज जैसे-जैसे अंतरिक्ष की कक्षाएं उपग्रहों से भर रही हैं, तकनीकें अधिक शक्तिशाली हो रही हैं और कई नए देश व एजेंसियां इसमें शामिल हो रही हैं, वैसे-वैसे दुनिया के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में हमारे फैसले बिल्कुल साफ होने चाहिए। हमें टकराव के बजाय सहयोग, थोड़े समय के फायदे के बजाय टिकाऊ विकास और किसी को बाहर करने के बजाय सबको साथ लेकर चलने का रास्ता चुनना होगा। भारत का अंतरिक्ष अभियान इसी सोच और सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने समिट में कहा कि भारत का नजरिया वसुधैव कुटुम्बकम् यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार से जुड़ा हुआ है और अब इस भावना को धरती से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत



अंतरराष्ट्रीय कानूनों, बातचीत और आपसी सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित, शांत और टिकाऊ अंतरिक्ष व्यवस्था का मजबूती से समर्थन करता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिक आंकड़ों और जानकारीयों को पूरी ईमानदारी तथा खुलेपन के साथ सभी लोगों को भलाई के लिए साझा किया जाना चाहिए। भारत का पूरा अंतरिक्ष सफर इसी लोक-कल्याणकारी सोच को दर्शाता है और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है।

पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वैश्विक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इसरो ने अपनी बेहतरीन और कम लागत

वाली सटीक उड़ानों के दम पर पूरी दुनिया में जबरदस्त सम्मान कमाया है। इसरो की क्षमताएं सीधे तौर पर हमारे किसानों और मछुआरों के जीवन को आसान बना रही हैं। यह मौसम की भविष्यवाणी करने, आपदा प्रबंधन और सटीक दिशा-दूरी बताने (नेविगेशन) में लगातार देश और दुनिया की सेवा कर रहा है।

भारत के भरोसेमंद रॉकेटों के जरिए अब तक 34 देशों के 430 से अधिक उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इसरो की तकनीक और साझेदारियां केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के काम आ रही हैं। इस भरोसे के पीछे भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की पीढ़ियों की दिन-रात की कड़ी मेहनत और पसीना है, जिन्होंने एक-एक मिशन को सफल बनाकर भारत को दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष देशों की कतार में गर्व से खड़ा किया है।भारत की ऐतिहासिक कामयाबियों और भविष्य के बड़े लक्ष्यों को सामने रखते हुए पीएम मोदी ने कई अहम जानकारीयां साझा कीचंद्रयान-3 मिशन के जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना।सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए आदित्य एल-1 मिशन

अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डटा हुआ है और आंकड़े जुटा रहा है।बीते साल एक भारतीय नागरिक ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ड्रुस) का दौरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।भारत ने साल 2035 तक अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है।साल 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर भेजने के संकल्प पर काम तेजी से जारी है।इन सभी अभियानों का एकमात्र मुख्य उद्देश्य यह है कि विज्ञान और तकनीक का पूरा लाभ समस्त मानव जाति तक आसानी से पहुंचे।पीएम मोदी ने बताया कि आज इसरो की शानदार विशेषज्ञता के साथ-साथ भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय उद्यमों की ऊर्जा इसरो की तकनीकी शक्ति से मिलकर देश को नई ऊंचाई दे रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 1960 के दशक में जब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब से फ्रांस भारत का एक बेहद भरोसेमंद साझेदार रहा है। आज दोनों देशों का यह साझा काम पृथ्वी के अध्ययन (अर्थ ऑब्ज़र्वेशन) से लेकर कई आधुनिक तकनीकों तक फैला हुआ है, जो विज्ञान की शक्ति को मानवता के कल्याण से जोड़ता है।

देश में ही बनेंगे सुखोई जेट और टर्बोप्राप

ब्रिक्स से पहले 105 विमानों की डील पर भारत-रूस के बीच बातचीत



नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत और रूस के बीच 105 जेट्स पर समझौता हुआ है। जिसके तहत रूस, भारत को 105 जेट्स देगा।

दरअसल, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने गुरुवार को बताया कि देश की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के बीच 105

टर्बोप्राप और सुखोई सुपरजेट विमानों के स्वदेशी निर्माण को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है।

भारत की क्षेत्रीय

कनेक्टिविटी बिल्कुल अलग

नायडू ने स्पष्ट किया कि ये दोनों विमान भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (ग्रह) योजना की जरूरतों के बिल्कुल अनुकूल हैं। देश भर में कई नए हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं, जिन्हें आपस में जोड़ना बेहद जरूरी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन विमानों का

निर्माण जल्द से जल्द भारत में ही शुरू करना है ताकि घरेलू उड़ान नेटवर्क को मजबूती दी जा सके।

सैन्य रक्षा समझौतों से आएगी मजबूती

इस प्रस्तावित सौदे के तहत पिनैकल एयर और एयर केरल जैसे भारतीय ऑपरेटर्स को ये विमान सौंपे जाएंगे, जिससे दोनों देशों के संबंध पारंपरिक सैन्य रक्षा समझौतों से आगे बढ़कर नागरिक विमान निर्माण के क्षेत्र में और गहरे होंगे।

‘किन-किन कंपनियों के

साथ डील?

प्रस्तावित डीलस में पिनैकल एयर के लिए 50 ड्रु-114-300 विमान, एयर केरल के लिए 20 विमान और स्लीक एविएशन के साथ हुए रण (समझौता ज्ञापन) के तहत 35 और विमानों की योजना शामिल है।



रायपुर। महाराजा चक्रधर सिंह की कला-साधना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित 41वें अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह-2026 में इस बार कला और संस्कृति के विविध रंग एक साथ देखने को मिलेंगे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 14 से 23 सितम्बर तक आयोजित होने वाले इस दस दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ में स्थानीय प्रतिभाओं से लेकर देश-प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। (विस्तृत समाचार पेज-8 पर)

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत दौरे पर आएंगे चीनी राष्ट्रपति

नई दिल्ली। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शी जिनपिंग नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने शनिवार को भारत आएंगे। इस दौरान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।

भारत इस बार 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

इसी सिलसिले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे। अगर जिनपिंग नई दिल्ली आते हैं तो यह 2020 के सीमा विवाद और गलवान झड़प के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालयों ने भारत दौरे की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में भारत और चीन के सैनिक बलिदान हुए थे। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बेहद निचले



स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि, बीते कुछ महीनों में सैन्य और राजनयिक बातचीत के जरिए सीमा के कई तनाव वाले बिंदुओं से सेनाएं पीछे हटी हैं।

गलवान हिंसा के बाद दोनों

देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके। हाल ही में कजाकिस्तान के बिशकेक में हुए एससीओ सम्मेलन में दोनों नेता एक साथ मंच पर दिखे और हाथ भी मिलाया, लेकिन वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। अब दिल्ली में होने वाली संभावित बैठक को दोनों देशों के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।

शी जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा

सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन का दौरा किया था। इसके अलावा, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म (डब्ल्यूएमसीसी) और दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच भी उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। इन्हीं बैठकों के आधार पर दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात की जमीन तैयार की गई है। वहीं, लद्दाख में भले ही तनाव कुछ कम हुआ हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बना हुआ है। चीन अरुणाचल को जूंगनान यानी दक्षिणी तिब्बत बताता है।

ब्रिक्स पर चिदंबरम को भाजपा का करारा जवाब

नईदिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के उस बयान पर तीखा पलटवार किया, जिसमें उन्होंने भारत द्वारा आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर टिप्पणी की थी। भंडारी ने विपक्ष की मानसिकता की तुलना नाराज़ फूफा से की। मीडिया से बात करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष 'FOMO' (कुछ छूट जाने का डर) से ग्रस्त है और आरोप लगाया कि जब भी देश का वैश्विक कद बढ़ता है, तो कांग्रेस अक्सर राष्ट्रीय उपलब्धियों का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगर आप आज कांग्रेस को देखें, तो भारत में हो रहे ब्रिक्स समिट का वे ठीक वैसे ही विरोध कर रहे हैं जैसे कोई नाराज़ फूफा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जब भी देश तरकी़ करता है या भारत का मान-सम्मान बढ़ता है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका विरोध ही करेगी। भाजपा प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं ने यह मान लिया है कि वे न तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखेंगे और न ही ब्रिक्स समिट को मेज़बानी करते हुए।

निशिकांत ने राहुल के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध की मांग की

नईदिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश जाने पर रोक लगाने और उनकी संसदीय सदस्यता खत्म करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े एक पत्र का हवाला दिया। झारखंड के देवघर में इस मुद्दे पर बात करते हुए, दुबे ने 1955 के एक पत्र का जिक्र किया जिसमें नेहरू ने कथित तौर पर कम्युनिस्ट विचारधारा को देशद्रोह के बराबर बताया था और इसे गांधी के विदेशी दौरों से जोड़ा था। दुबे ने एक्स पर लिखा कि नेहरू जी के शब्दों के अनुसार, क्या राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म नहीं की जानी चाहिए और उनके विदेश जाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए? कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब है देशद्रोह; विदेश में सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब जी को स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया था।



मायावती ने भतीजे को सभी जिम्मेदारियों से किया मुक्त

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ के बृहस्पतिवार को राजनीति और सामाजिक जीवन से संन्यास लेने के ऐलान के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और सिद्धार्थ के दामाद आकाश आनन्द को पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह अभी इसी वक्त राजनीति और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहे हैं और संन्यास तो बहुत छोटी चीज है अगर उन्हें कभी मायावती के लिए



अपनी जान भी देनी पड़े तो वह उनके लिए फख्र की बात होगी। हालांकि सिद्धार्थ द्वारा देरी के लिये क्षमा प्रार्थी नोट के साथ की गई इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद मायावती ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर सिद्धार्थ को अपने दामाद आकाश आनन्द के उच्चल भविष्य के साथ ही बसपा तथा बहुजन आंदोलन की जरा सी भी चिंता होती तो वह बिना देर किए बुधवार को ही राजनीति से संन्यास की घोषणा कर देते।

स्टालिन ने आपातकाल के दौरान झोले दर्द को याद किया

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कणगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में कड़े कानून 'मीसा' से जुड़ी टिप्पणियों के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा किए गए ‘‘जबड़े के इशारे’’ पर बृहस्पतिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और आपातकाल के दौरान जेल में अपने साथ हुई गंभीर शारीरिक ज्यादती को याद किया। विजय द्वारा सरकरिया आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दशकों पुराने भ्रष्टाचार के आरोप उठाए जाने पर स्टालिन ने उनकी आलोचना की और इन आरोपों को ‘‘राजनीति से प्रेरित झूठ’’ करार दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप उन लोगों द्वारा फैलाए गए, जो पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के प्रति लंबे समय से नाराजगी रखते थे। मीसा के दौर के अपने इतिहास का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्वीकार किया कि मीसा के इतिहास को लेकर विजय की बात सही थी।



भाजपा ने मोर्चों के प्रभारी बदले बैजयंत को ओबीसी का प्रभार

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने विभिन्न मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हुए वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग मोर्चों की कमान सौंपी है। जानकारी के मुताबिक, हरीश द्विवेदी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, डी. पुरंदेश्वरी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा का प्रभारी संजय भाटिया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बैजयंत पांडा को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी लाल सिंह आर्य को दी गई है, जबकि सतीश पूनिया अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा के प्रभारी होंगे। पार्टी ने गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया है। नए प्रभारियों की नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।



प्रमुख समाचार

नीरज कुमार दुबे

भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस वर्ष भारत ने सम्मेलन के लिए लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित जनकेंद्रित दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है। हम आपको बता दें कि 11 सदस्यीय ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी, जलवायु, वित्तीय सहयोग तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दे

प्रमुख रहेंगे।

सम्मेलन का औपचारिक कार्यक्रम 12 सितंबर को दोपहर दो बजे सदस्य देशों के नेताओं के भारत मंडपम पहुंचने से शुरू होगा। दो बजकर 35 मिनट पर वैश्विक शासन को अधिक समावेशी बनाने और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बंद करमें में बैठक होगी। शाम चार बजकर 25 मिनट पर नेता भारत की नवाचार प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 5 बजकर 5 मिनट पर सामूहिक फोटो और 5 बजकर 10 मिनट पर संयुक्त वृक्षारोपण होगा। शाम साढ़े सात बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजकीय रात्रिभोज दिया जाएगा।

13 सितंबर को सुबह नौ बजकर 55 मिनट पर सदस्य देशों के साथ

साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेता पहुंचेंगे। दस बजकर 35 मिनट पर सामूहिक फोटो होगा और दस बजकर 50 मिनट पर ‘लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के माध्यम से समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने’ विषय पर खुला सत्र होगा। सम्मेलन के अंत में नई दिल्ली घोषणा जारी किए जाने की संभावना है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण घोषणा पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच मतभेदों की प्रवृभूमि में।

हम आपको यह भी बता दें कि सम्मेलन से एक दिन पहले, 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति



व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेरिकयान के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पुतिन के साथ बातचीत में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रमुख विषय रह सकते हैं। रूस ने सुखोई-57 लड़ाकू विमान की बिक्री को बातचीत के एजेंडे में होने की पुष्टि की है। अंतिम एस-400 प्रणाली की आपूर्ति, अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस

मिसाइलों के विकास और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा संभावित है। दोनों पक्ष व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी विचार कर सकते हैं।

वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेजेरिकयान के साथ बातचीत में चाबहार बंदरगाह पर व्यापार और आर्थिक सहयोग तथा पश्चिम एशिया की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण विषयों में रहेंगे। भारत समुद्री व्यापार और जहाजरानी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय तनाव को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से कम करने पर जोर दे सकता है। चाबहार के संचालन और भारत-ईरान व्यापार के विस्तार से

जुड़े नए कदमों की भी संभावना है।12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक पर सबसे अधिक निगाहें रहेंगी। सात वर्ष बाद शी की भारत यात्रा और 2020 के सीमा संघर्ष के बाद दोनों नेताओं की यह महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। सीमा पर व्यापार और आर्थिक सहयोग रेखा की पश्चिम एशिया की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण विषयों में रहेंगे। भारत समुद्री व्यापार और जहाजरानी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के केंद्र में रह सकती बातचीत और कूटनीति के माध्यम से कम करने पर जोर दे सकता है। चाबहार के संचालन और भारत-ईरान व्यापार के विस्तार से

तथा अन्य सदस्य और आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ मोदी की मुलाकातों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री संपर्क, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय संकटों पर चर्चा संभावित है। माना जा रहा है कि भारत ब्रिक्स के भीतर व्यावहारिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने और वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका मजबूत करने का प्रयास करेगा।देखा जाये तो इस सम्मेलन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि अगस्त के अंत में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान मोदी की पुतिन, पेजेरिकयान और शी के साथ मुलाकात हो चुकी है।



हब
निक्स उद्योग

छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर अब तेजी से देश के उभरते टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योगों के अनुकूल नीतियां और तेज प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र को हाईटेक निवेश का नया गढ़ बना दिया है। अब नवा रायपुर केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी डिस्टिन्शन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों के कारण देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हो रही हैं। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, एआई आधारित तकनीक, टेलीकॉम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों के लिए यहां मजबूत संभावनाएं तैयार हुई हैं।

“ हम अब इंटरनेट की 6G और 7G तकनीक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, कि इसके लिए माइक्रोचिप हमारे देश में ही तैयार होंगे और नवा रायपुर अटल नगर में हमारे इंजीनियर और विशेषज्ञ इसे आकार देंगे।

- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



नवा रायपुर में तैयार होगा भविष्य का डिजिटल भारत

मुख्यमंत्री विष्णु पद साय ने हाल ही में नवा रायपुर में अत्याधुनिक
समीककवर्त निर्माण इकाइयों और हाईवेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स
को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ अब तकनीकी क्रांति के नए दौर में
प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाली समय में देश में उपयोग
होने वाली अत्याधुनिक तकनीक समकनीकों के लिए आवश्यक चिप्स और
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भातत ही हैं तैयार किए जाऐगे और इसमें
नवा रायपुर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि
विकासित भारत के निर्माण में विकासित छत्तीसगढ़ की भूमिका
लगतातर मजबूत हो रही है। तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र
में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व के
विकासित देशों ने तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता
देकर ही आर्थिक शक्ति हासिल की है और अब छत्तीसगढ़ भी उसी
दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।



देश का पहला एआई केन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

नवा रायपुर अटल नगर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आकार ले रहा है। यह विशेष क्षेत्र पूरी तरह से AI और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास, संचालन और नवाचार को समर्पित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को रैकबैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह स्थल लगभग 6 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसमें 1.5 लाख वर्ग फुट का एक विशाल और अत्याधुनिक डेटा सेंटर शामिल होगा। आगे की योजना में नार और हार्ड-डिस्क डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिनकी संयुक्त क्षमता 80 मेगाबाइट होगी। यह क्षमता देश के कई राज्यों के डेटा सेंटरों की तुलना में अधिक है। यह क्षेत्र नार और हार्ड-डिस्क डेटा सेंटरों को विकसित करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस परियोजना को 'नवा छत्तीसगढ़ की नई शुरुआत' बताया। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य के युवाओं को नए रोजगार के अवसर देगा और छत्तीसगढ़ को एक तकनीकी पहचान प्रदान करेगा। यह पहल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों की भी मजबूती देगी।



हाईटेक प्लांट्स से युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर

नवा रायपुर में किसित हो रहे इन आधुनिक उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावनाएं बनी हैं। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईआई, ऑटोमोशन और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में नवा रायपुर देश के प्रमुख टेक्निकल टैलेंट हब के रूप में उभर सकता है। यहां बनने वाले हाईटेक प्लांट्स से स्थानीय युवाओं को देश छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें अपने ही राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों में काम करने का अवसर मिलेगा।



ईवी व पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिलेगा बड़ावा

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार नवा रायपुर में प्रस्तावित नई परियोजनाएँ केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं रहेंगी। यहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, डीवी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइस और भविष्य की संसार तकनीकों से जुड़े बड़े उत्पादन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिकल सेक्टर और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में सहायक उद्योगों, स्टार्टअप और रिसर्च आधारित कंपनियों के लिए भी बड़े अवसर तैयार होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक विविधियों में तेजी आएगी और हजारों छोटे व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा।



सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मंजूरी

नवा रायपुर अटल नगर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मंजूरी दी गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित SEZ 10.13 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होगा और इसमें राज्य का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। इस स्वर्ण को 'पॉलिमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' को विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से नवा रायपुर में हाईटेक उद्योगों के लिए एक नया केंद्र विकसित होगा, जिससे लगभग 1,300 स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह कदम राज्य में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करने और तकनीकी भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

तेज प्रशासनिक फैसलों ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

राज्य सरकार और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को तेजी से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों को कम समय में भूमि, बिजली,

कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक स्वीकृतियां मिलने से कंपनियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ केवल खनिज

और इस्पात उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकी उद्योगों का भी नया केंद्र बनकर उभर रहा है।

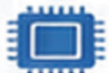
नवा रायपुर के सेक्टर-5 में डेढ़ लाख वर्ग फीट जमीन पर प्लांट



सीएम सायन ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में आयोजित एक इवेस्टर्स मीट में राज्य के अधिकारियों की मुलाकात पोलीमैटेक के प्रबंधन से हुई थी, उस दौरान कंपनी ने एस्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई थी। जिसके बाद उद्योग विभाग और एनआरडीए ने 45 दिनों के अंदर नवा रायपुर के सेक्टर-5 में डेढ़ लाख वर्ग फीट भूमि उपलब्ध कराई।

नवा रायपुर : भविष्य की तकनीक का मजबूत आधार

आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, तेज प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उद्योगों के अनुकूल नीतियों के कारण नया रायपुर अब देश के उपर टेक्नोलॉजी शहरों में तेजी से शामिल हो रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को आने वाले वर्षों में देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग हब बनाना है।



सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप निर्माण



पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और
ईवी टेक्नोलॉजी



एआई और भविष्य की
प्रौद्योगिकियों में अग्रणी



हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर



संक्षिप्त समाचार

पोरा तिहार पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के पारंपरिक एवं लोक आस्था के प्रमुख पर्व पोरा तिहार के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, कृषि परंपरा और ग्रामीण जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हमारी माटी, खेती-किसानी और पशुधन के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता की भावना को प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोकपर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव हैं। पोरा तिहार के माध्यम से हमारी परंपराएं, लोकमान्यताएं और संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यह पर्व समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का संदेश भी देता है। श्री ओपी चौधरी ने कामना की कि पोरा तिहार प्रदेश के सभी परिवारों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। किसानों के खेतों में भरपूर फसल हो और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास एवं समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े।

नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर शासकीय कार्यालय रहेंगी बंद

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के तहत रायपुर जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। यह अवकाश रायपुर जिले, शहर (राजधानी) स्थित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में लागू होंगे। जारी आदेश के अनुसार नुआखाई पर्व के लिए 15 सितंबर 2026 (मंगलवार), महाअष्टमी के लिए 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) तथा गोवर्धन पूजा (दीपावली के दूसरे दिन) के लिए 9 नवंबर 2026 (सोमवार) को स्थानीय अवकाश रहेगा। जारी आदेश के अनुसार ये अवकाश रायपुर जिले के अंतर्गत संबंधित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं पर लागू होंगे।

डीएलएड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष पूरक / अवसर परीक्षा की समय सारणी जारी

रायपुर। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड) प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पूरक /अवसर परीक्षा वर्ष 2026 की समय सारणी बुधवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने जारी कर दी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अनुसार डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड) नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के विषय (प्रथम वर्ष) की परीक्षा 16.11.2026 से 02.12.2026 तक व डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड) नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के विषय (द्वितीय वर्ष) की परीक्षा 17.11.2026 से 30.11.2026 तक सुबह 9ः00 बजे से दोपहर 12ः15 तक आयोजित की गई है। विस्तृत समय-सारणी मण्डल की वेबसाइट www.cgbsse.nic.in पर उपलब्ध है।

10वीं-12वीं के छात्र ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 10 अक्टूबर तक करें आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की नवंबर 2026 सत्र की हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक सामान्य शुल्क के साथ प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। तय समय में आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्र-छात्राएं 13 से 17 अक्टूबर 2026 तक 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा और प्रवेश से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र अपने नजदीकी मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र से आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा आवेदन फॉर्म छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित अध्ययन केंद्र में जमा करना होगा।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में होगी 1812 संविदा शिक्षकों की भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 1812 संविदा पदों पर भर्ती होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती का अभी केवल संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है इसलिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण, सिलेबस, आवेदन फीस और आवेदन की अंतिम तारीख की विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सितंबर 2026 में शुरू होगी। परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के जरिए होने की संभावना है। भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित जिले की प्रबंधन और संचालन समिति, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होगी। उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल विभाग ने संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। जिसमें पदों की योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण, सिलेबस, फीस और परीक्षा योजना की जानकारी दी जाएगी। कुल 1812 संविदा पद हैं जिनमें सहायक शिक्षक के 590, प्रयोगशाला सहायक के 170, शिक्षक अंग्रेजी के 106 और व्याख्याता वाणिज्य के 104 पद शामिल हैं। व्याख्याता प्रधानपाठक के कुल 511 पद हैं जिनमें व्याख्याता हिन्दी 51, अंग्रेजी 65, संस्कृत 47, भूगोल/अर्थशास्त्र 5, इतिहास/राजनीति 6, सामाजिक विज्ञान 52, गणित 49, जीव विज्ञान 39, वाणिज्य 104, रसायन 44 और भौतिक के 53 पद हैं। प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के 27 और पूर्व माध्यमिक शाला के 24 पद हैं। इसके अलावा शिक्षक और अन्य पदों पर कुल 1301 पद हैं।

राजधानी/छत्तीसगढ़

केंद्रीय मंत्री चौहान आज जेठ में करेंगे ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ

122 करोड़ रुपए से अधिक के 39 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व भूमिपूजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, आवास, आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन 11 सितंबर को सक्ती जिले के ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस वृहद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, विकसित भारत-जी राम जी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं, अभियानों और पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास

गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित राज्य शासन के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य में नवनिर्मित 2 लाख आवासों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा। कार्यक्रम में हितग्राहियों को खुशियों की चाबी प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन एवं सैल्फ जियो-टैग रिपोर्ट प्रणाली का शुभारंभ होगा। तकनीकी नवाचार पर आधारित यह व्यवस्था आवास निर्माण की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं



शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से नदियों एवं उनकी सहायक जलधाराओं के पुनरुद्धार, संरक्षण एवं पुनर्जीवन को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सुध्वर बाड़ी अभियान के जरिए निजी से सामुदायिक भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण परिवारों के लिए आय के स्थायी स्रोत सृजित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण

आजीविका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत 270 नए इंटोग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) का विमोचन किया जाएगा। इन क्लस्टरों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की कृषि आधारित आजीविका को अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण बनाने का प्रयास होगा। कृषि से जुड़े विभिन्न गतिविधियों के एकीकरण के जरिए ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर टिकाऊ आजीविका के अवसर विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा।

कार्यक्रम में अथ उद्यम-आजीविका से उद्यमिता की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत चैलेंज फंड इवेंट का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आजीविका

गतिविधियों से आगे बढ़ाकर उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है। इस अवसर पर ग्रामीण आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली रानी मिस्त्री, लखपति दीदियों एवं झोन दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान ग्रामीण महिलाओं को उपलब्धियों को पहचान देने के साथ अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के लिए प्रेरित करेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की 5 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में लगभग 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

पदोन्नति के पदों पर संविदा नियुक्तियों का विरोध

■ नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन

रायपुर। पदोन्नति के पदों पर की गई संविदा नियुक्तियों को निरस्त करने और नर्सिंग संवर्ग की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने तीन दिवसीय सार्केतिक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के पहले दिन गुरुवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर परिसर में संघ के पदाधिकारियों और नर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

संघ का कहना है कि लंबे समय से नर्सिंग संवर्ग की कई मांगें लंबित हैं, लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से इनके निराकरण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। इन्हीं मांगों को लेकर तीन दिवसीय सार्केतिक प्रदर्शनों के जरिए शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

एसोसिएशन की प्रमुख मांग नर्सिंग डेमोंस्ट्रेटर और सहायक प्राध्यापक के पदों पर की गई संविदा नियुक्तियों को निरस्त करना है। संघ ने मांग की है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग

और एमएससी नर्सिंग की योग्यता रखने वाले नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों को बरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति दी जाए। संघ ने बताया कि नर्सिंग डेमोंस्ट्रेटर के 22 और सहायक प्राध्यापक के 18 पदों पर सीधी भर्ती के आदेश स्वीकृत होने के बावजूद अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। एसोसिएशन ने इन पदों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के पात्र नर्सिंग कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देने की मांग की है।

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के ग्रेड-पे और वेतनमान में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को शासन स्तर पर भेजकर जल्द स्वीकृति देने की मांग की है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदमान से संबंधित घोषणा के अनुरूप आदेश जारी करने की मांग भी रखी गई है। संघ ने नर्सिंग अलाउंस 7,200 रुपये और वॉशिंग अलाउंस 1,800 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की है। वहीं संविदा और कलेक्टर दर पर कार्यरत स्टाफ नर्सों के लिए न्यूनतम 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित करने की मांग भी शामिल है।

हसदेव के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर कांग्रेस के सवाल

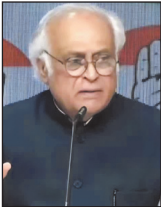
■ 4 हजार एकड़ जंगल, 10 लाख पेड़ों और हथी कॉरिडोर पर जताई चिंता

रायपुर। हसदेव-अरण्य के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नीलामी को अड़ानी कंपनी से जोड़ते हुए कांग्रेस ने कहा कि इस नीलामी का विजेता कौन है इसमें कोई रहस्य नहीं है। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को पर्यावरण विनाश का उदाहरण बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि तारा कोल ब्लॉक का बड़ा हिस्सा घने जंगल से घिरा है और यहां खनन शुरू होने से लाखों पेड़ों की कटाई के साथ हाथियों के आवागमन पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार ने जैव विविधता से भरपूर हसदेव अरण्य इकोसिस्टम में तारा कोल ब्लॉक की नीलामी की है। कांग्रेस के मुताबिक, इस नीलामी में विजेता कंपनी CG Syn-Gas and Chemicals Limited है, जो Mundra Synenergy Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सर्मिस्डियरी है। वहीं Mundra Synenergy Limited खुद Adani Enterprises Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

कांग्रेस ने तारा ब्लॉक की नीलामी के विरोध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्ताव का भी हवाला दिया है। जयराम रमेश के मुताबिक, 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य में किसी भी नए कोल ब्लॉक के आवंटन या नीलामी पर रोक की मांग की थी।

कांग्रेस का कहना है कि 16 जुलाई 2023 को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया था कि हसदेव अरण्य में किसी नई खदान के आवंटन या विकास की



आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि इन परिस्थितियों के बावजूद तारा कोल ब्लॉक की नीलामी कैसे हुई। जयराम रमेश ने अपने बयान में दावा किया कि 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने तारा समेत 40 कोल ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया से डीनोटिफाई कर दिया था। कांग्रेस का सवाल है कि जब तारा कोल ब्लॉक को पहले नीलामी प्रक्रिया से बाहर किया गया था, तो अब दोबारा इसकी नीलामी क्यों की गई।

कांग्रेस ने तारा ब्लॉक का नाम बदलकर ‘तारा (रिवाइज्ड)’ किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश का कहना है कि नाम बदलने से जमीन पर पड़ने वाला पर्यावरणीय प्रभाव नहीं बदल जाता।

कांग्रेस के मुताबिक तारा कोल ब्लॉक करीब 5 हजार एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 4 हजार एकड़ से ज्यादा हिस्सा घने जंगल का बताया गया है। कांग्रेस का दावा है कि खनन के लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो सकती है। तारा में खनन को लेकर कांग्रेस ने हाथियों के आवागमन पर भी गंभीर चिंता जताई है। कांग्रेस का कहना है कि तारा ब्लॉक लेमरू एलीफेंट रिजर्व के आसपास स्थित है और यहां खनन होने से हाथियों के आवाजाही के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं।

कांग्रेस के अनुसार, हसदेव अरण्य क्षेत्र कई वन्यजीवों और अन्य प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। तारा में खनन से इन प्रजातियों पर अतिरिक्त खतरा पैदा हो सकता है। कांग्रेस ने इनमें कुछ प्रजातियों के पहले से ही गंभीर रूप से संकटग्रस्त होने का दावा किया है। जयराम रमेश ने कम्पेन्सेटरी अफरिस्टेशन यानी जंगल की कटाई के बदले दूसरे स्थान पर पेड़ लगाने की व्यवस्था पर भी



स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति की सही और गलत में अंतर करने की क्षमता को प्रभावित करता है। नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को दोषी मानने के बजाय उसके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने हुए कार्टेसिलिंग और आवश्यकता पड़ने पर उपचार उपलब्ध कराना चाहिए। अधिक नशे से मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। डेका ने कहा कि नशे से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन में परीक्षा का दबाव,

■ छत्तीसगढ़ में आरपीआई की एंटी!

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी में हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी समाजों को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने संकेत दिया कि यदि पार्टी प्रदेश में मजबूत होगी तो भाजपा के साथ 4 से 5 सीटों पर गठबंधन को लेकर विचार किया जा सकता है।

रामदास अठावले ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आरपीआई छत्तीसगढ़ में अपना संगठन खड़ा करने और उसे मजबूत करने पर काम करेगी। पार्टी का फोकस सभी समाजों को साथ लेकर चलने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि

सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक और विशाल वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई महज दूसरे स्थान पर पेड़ लगाने से नहीं की जा सकती।

कांग्रेस ने दावा किया है कि स्थानीय आदिवासी और अन्य समुदाय पिछले करीब 15 वर्षों से हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। ग्राम सभा के प्रस्तावों से लेकर जन अभियानों, धरनों और विरोध मार्च तक के जरिए जंगल और उससे जुड़ी आजीविका की सुरक्षा की मांग उठाई जाती रही है। इन आंदोलनों में रायपुर तक निकाला गया मार्च भी शामिल है।

कांग्रेस के सवाल-

● जब 2022 में विधानसभा ने हसदेव में नई खदानों की नीलामी रोकने का प्रस्ताव पारित किया, तो तारा की नीलामी क्यों हुई ?

● जब 2023 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई खदान की जरूरत नहीं होने की बात कही, तो फिर तारा ब्लॉक आगे कैसे बढ़ा ?

● जब तारा समेत 40 ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया से डीनोटिफाई किए गए थे, तो दोबारा नीलामी क्यों की गई ?

● ‘तारा (रिवाइज्ड)’ नाम दिए जाने के पीछे क्या वजह है ?

● 4 हजार एकड़ से ज्यादा घने जंगल और लाखों पेड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव की भरपाई कैसे होगी ?

● खनन से लेमरू क्षेत्र के हाथियों के आवागमन पर पड़ने वाले असर को कैसे रोका जाएगा ?

फिलहाल तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर रियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने जहां इसे हसदेव-अरण्य और उसकी जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बताया है, वहीं अब नजर इस बात पर है कि केंद्र और राज्य सरकार कांग्रेस के इन आरोपों और सवालों पर क्या जवाब देती हैं।

करियर की चिंता, असफलता का भय और अपेक्षाओं का बोझ जैसी परिस्थितियां अभी रहती हैं। इनसे बचने के लिए नशे का सहारा लेना समाधान नहीं है। समस्या से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही वास्तविक साहस है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, समय की पाबंदी और नियमित अध्ययन को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पढ़ने की आदत से ज्ञान के साथ-साथ विभिन्न विषयों के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। राज्यपाल ने डिजिटल एडिक्शन को भी गंभीर चुनौती बताते हुए युवाओं से डिजिटल माध्यमों का संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हार्टफुलनेस आश्रम, हैदराबाद के संचालक श्री त्रिलोचन चावला ने नशा मुक्तिके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया।

3

विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ

122 करोड़ रुपए से अधिक के 39 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व भूमिपूजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, आवास, आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन 11 सितंबर को सक्ती जिले के ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस वृहद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, विकसित भारत-जी राम जी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं, अभियानों और पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में अथ उद्यम-आजीविका से उद्यमिता की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत चैलेंज फंड इवेंट का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आजीविका



संगठन के विस्तार के बाद चु न। वी समीकरणों को देखते हुए भाजपा के साथ सीटों को लेकर बातचीत की

संभावना बन सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा के साथ अपने राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी मजबूत होने के बाद गठबंधन को लेकर आगे विचार किया जाएगा।

वहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर अठावले ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष का काम अच्छा कर

रहे हैं। उन्हें विपक्ष का नेता ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को झूट नहीं बोलना चाहिए।

अठावले ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को मुश्किल बताते हुए कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का भरोसा है।

छत्तीसगढ़ में आरपीआई का विस्तार होने और भाजपा के साथ संभावित सीट गठबंधन का संकेत प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा है। हालांकि, अठावले ने फिलहाल गठबंधन को अंतिम रूप देने की बात नहीं कही है। उनका कहना है कि पहले पार्टी को प्रदेश में मजबूत किया जाएगा और इसके बाद चुनावी परिस्थितियों के अनुसार सीटों पर विचार होगा।

भाजपा के सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ‘नाराज फूफा’ बताए जाने पर बिफरे बैज

रायपुर। भाजपा के सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ‘नाराज फूफा’ बताए जाने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नाराज फूफा बताया गया है। इस पर मीडिया के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि फूफा किसे कह रहे हैं, असली फूफा तो आप लोग (भाजपा) हैं। नकली पेट्रोल बेचा जा रहा है, पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़े हुए हैं। डबल इंजन की सरकार से जनता परेशान है। वहीं साय कैबिनेट के फैसलों पर दीपक बैज ने कहा कि सरकार कई कैबिनेट बैठक कर ले, लेकिन देश के साथ प्रदेश की जेन जी को नहीं साथ सकती। जेन जी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग चौपट हो चुके हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है।

दीपक बैज ने कहा कि सरकार कई कैबिनेट बैठक कर ले, लेकिन देश के साथ प्रदेश की जेन जी को नहीं साथ सकती। जेन जी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग चौपट हो चुके हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की यात्रा को लेकर बैज ने कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। पीएम मोदी पेट्रोल-डीजल बचाने की बात करते हैं, और इधर 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर यात्रा निकाल रहे हैं। इथेनॉल

मिलाकर डुप्लीकेट पेट्रोल दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गोधरा कांड से लेकर जेन जी आंदोलन तक यही चल रहा है। महंगाई चरम पर है, और आम जनता त्रस्त है। नौकरियां नहीं हैं। भाजपा लोकतंत्र को

कुचलने का काम कर रही है, पहले भाजपा को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। धोखा देने और जुमलेबाजी के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को क्षेत्र पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए जाने पर पीसीसी चीफ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। इस वर्ष कम बारिश हुई, फिर भी कई शहरों में पानी भर गया। कई क्षेत्रों में तो नाब चला रही है। स्थिति बन गई। व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी है। यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों का भी है, आम जनता को सुविधा देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है।

वहीं कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण चल रहा है। आज से तीन दिन तक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। उद्योगों के महाकुंभ को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार महाकुंभ कर ले या मेला लगा ले। सरकार के पास उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। उद्योगपति से लेकर आम जनता तक परेशान है। दो उद्योगपतियों के लिए यहां के खनिज संसाधनों को बेचा जा रहा है।

न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील खोरपा जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईशतहार //

ग्राम खोरपा प.ह.नं. 09 रा.प्र.क्र. / अ-59 वर्ष 2025-26 एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कार्यालय प्राचार्य, का पत्र शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खोरपा जिला रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/ औप्रस/खोरपा/स्थाप/पु.ध./2025/271 खोरपा दिनांक 28.11.2025 के द्वारा ग्राम खोरपा प.ह.नं. 09 तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खरसा नंबर 1975 का भाग, 2214 का भाग, 2215 का भाग रकबा क्रमशः 0.84 हे०, 2.25 हे०, 0.35 हे० कुल खरसा नंबर 03 कुल रकबा 3.44 हे० भूमि को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खोरपा के संस्था भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने हेतु पत्र माननीय कलेक्टर महोदय रायपुर के समक्ष पेश किया गया है जो अनुविभागीय अधिकारी (आ) अभनपुर के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। तत्संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचारणीय है।

अतः उक्त भूमि आबंटित किये जाने पर जिस किसी व्यक्ति / संस्था/समूह को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 22/09/2026 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं, नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से आज दिनांक 08/09/2026 को जारी किया गया।

**नायब तहसीलदार
उप तहसील खोरपा**

जी-262703193/2

ब्रिक्स में पीएम मोदी की कूटनीति देखेगी दुनिया

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से दुनिया को यह संदेश देते रहे हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। अब यही संदेश उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी कसौटी बन गया है। एक तरफ रूस-यूक्रेन युद्ध अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, दूसरी ओर पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने खाड़ी देशों को भी सीधे संकट में डाल दिया है। ऐसे समय में दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता का बड़ा प्रदर्शन भी बनने जा रहा है। ब्रिक्स में रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे परस्पर विरोधी हितों वाले देश एक साथ मौजूद होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर मोदी-पुतिन मुलाकात पर है। हाल ही में एससीओ सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से साफ कहा था कि अब युद्ध को आगे बढ़ाने की बजाय उसे खत्म करने का रास्ता तलाशना चाहिए। भारत और रूस के दशकों पुराने मजबूत रिश्तों के बीच मोदी का यह संदेश काफी महत्वपूर्ण है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी के पास एक और मौका होगा कि वह रूस के साथ अपनी दोस्ती कायम रखते हुए पुतिन को बातचीत और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम आपको यह भी बता दें कि इस दिशा में भारत केवल रूस से बात नहीं कर रहा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर हाल में कीव गए और यूक्रेनी नेतृत्व के साथ बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है और युद्ध को समाप्त करने में उपयोगी विचारों पर काम करने के लिए तैयार है। यानी मोदी सरकार की रणनीति किसी एक पक्ष को चुनने की नहीं, बल्कि दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखकर शांति की गुंजाइश बचाए रखने की है। वहीं पश्चिम एशिया में यही नीति और भी कठिन है। हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के क्रम में बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, जॉर्डन और दूसरे देशों को भी अपनी सैन्य कार्रवाई के दायरे में ला दिया। ईरान का तर्क था कि वह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन उन देशों की संप्रभु सीमाओं के भीतर पहुंचे जहां ये ठिकाने मौजूद हैं। जुलाई में भी ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य प्रतिय्ञानों को निशाना बनाने की कार्रवाई जारी रखी। यहीं मोदी की कूटनीति की असली परीक्षा सामने आती है। युद्ध के बीच उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की थी और साफ कहा था कि भारत सभी मुद्दों का समन्धान संवाद और कूटनीति से चाहता है। साथ ही उन्होंने ऊर्जा और व्यापार के निर्बाध आवागमन तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को भारत की प्राथमिकता बताया। दूसरी ओर उन्होंने यूआई, बहरीन, सऊदी अरब और कतर के नेताओं से अलग-अलग बातचीत कर उनके खिलाफ हुए हमलों की निंदा भी की थी। बहरीन के मामले में प्रधानमंत्री ने सीधे कहा था कि भारत हमलों की निंदा करता है और वहां के लोगों के साथ खड़ा है; सऊदी अरब और यूआई के संदर्भ में भी उन्होंने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को गंभीरता से लिया था। यही संतुलन मोदी की विदेश नीति की ताकत है। ईरान से संबंध भी चाहिए और खाड़ी अरब देशों का भरोसा भी; रूस से रणनीतिक साझेदारी भी बचानी है और पश्चिम से आर्थिक-तकनीकी रिस्ते भी मजबूत करने हैं। भारत के लिए यह केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। पश्चिम एशिया में करोड़ों भारतीयों के हित, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सीधे इससे जुड़ी है। मोदी ने ईरान से बातचीत में भी इसी व्यावहारिक प्राथमिकता को सामने रखा है।

ज्ञान/मीमांसा

बंगाल में भारतीय शिक्षा-दृष्टि को बल देने की अनुकरणीय घोषणा

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख शैक्षणिक प्रकल्प विद्या भारती के कम से कम एक हजार नए विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की घोषणा नहीं है, बल्कि इसे राज्य की शिक्षा-दृष्टि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। 4 सितंबर 2026 को सामने आई इस घोषणा के अनुसार अगले एक वर्ष में राज्य के प्रत्येक जिले, नगरपालिका और पंचायत तक विद्या भारती के विद्यालयों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विद्या भारती से जुड़े 313 विद्यालय संचालित होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने विद्या भारती के नेतृत्व को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने का भी निमंत्रण दिया है। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विद्या भारती आज देश के सबसे बड़े स्वीच्छिक शिक्षा-उत्क्रमों में से एक है। विद्या भारती के अपने उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसका नेटवर्क देशभर में 12,500 से अधिक विद्यालयों तक फैला हुआ है और इनमें 35 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके विद्यालय पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा खेल, संगीत, कला, विज्ञान, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों को भी शिक्षा का हिस्सा मानते हैं। हाल के समाचारों में देशभर में 12,000 से अधिक विद्यालयों और लगभग 10,000 बाल संस्कार केंद्रों का उल्लेख भी हुआ है। आंकड़ों में अंतर अलग-अलग वर्षों और संस्थागत गणना-पद्धतियों के कारण हो सकता है, लेकिन इससे विद्या भारती के व्यापक शैक्षिक विस्तार की तस्वीर स्पष्ट होती है।

विद्या भारती की विशेषता केवल यह नहीं है कि वह विद्यालयों की एक बड़ी शृंखला संचालित करती है। उसकी मूल अवधारणा शिक्षा को ज्ञान, संस्कार, चरित्र, राष्ट्रबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने की है। संस्था स्वयं अपने उद्देश्य में भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रभावना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रमुखता देती है। ग्रामीण, जनजातीय, सीमावर्ती और अपेक्षाकृत वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार भी उसके घोषित उद्देश्यों का हिस्सा है। यहीं से



पश्चिम बंगाल की नई पहल का व्यापक महत्व सामने आता है। बंगाल भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अत्यंत समृद्ध केंद्र रहा है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और अनेक महापुरुषों ने भारतीय चिंतन, शिक्षा, साहित्य और राष्ट्रचेतना को नई दिशा दी। इसलिए बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान, संस्कृति, मातृभाषा, स्थानीय इतिहास और राष्ट्रीय दायित्व को उचित स्थान देना किसी राजनीतिक आग्रह से अधिक व्यापक सांस्कृतिक आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। नीति का उद्देश्य विद्यार्थी में भारतीय होने के प्रति गहरी आत्मगौरव भावना विकसित करने के साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ने की बात करती है। इसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों, जनजातीय ज्ञान, पारंपरिक सीखने की पद्धतियों, योग, दर्शन, साहित्य, कृषि, वास्तुकला, नृतिकला, खेल और अन्य भारतीय योगदानों को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक ढंग से पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही गई है। नीति यह भी कहती है कि पाठ्यचर्या भारतीय और स्थानीय संदर्भ, संस्कृति, परंपरा, भाषा, भूगोल तथा ज्ञान-परंपराओं से जुड़ी होनी चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो विद्या भारती का शैक्षिक प्रयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक लक्ष्य एक-दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। अंतर यह है कि नीति एक राष्ट्रीय नीति-ढांचा उपलब्ध कराती है, जबकि विद्या भारती जैसा सामाजिक संगठन लंबे समय से विद्यालय स्तर पर मूल्यधारित शिक्षा का अपना प्रयोग करता आया है। इसलिए यदि पश्चिम बंगाल सरकार इस विस्तार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक विज्ञान, तकनीक, डिजिटल

शिक्षा, कौशल विकास और संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ती है तो इसका प्रभाव केवल नए विद्यालय खोलने तक सीमित नहीं रहेगा।

विद्यालय खोलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन अच्छे शिक्षक, प्रशिक्षित प्रधानाचार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना कहीं अधिक कठिन कार्य है। इसलिए इस पहल की सफलता संख्या से नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता से मापी जानी चाहिए। यदि नए विद्यालय केवल भवन बनकर रह गए तो लक्ष्य अधूरा होगा; यदि वे अच्छे शिक्षक और अच्छे नागरिक बनाने के केंद्र बनते हैं, तभी यह पहल ऐतिहासिक सिद्ध होगी। यहीं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अनेक सरकारी विद्यालय संसाधनों की कमी, शिक्षक-अभाव, आधारभूत सुविधाओं की कमजोरी, तकनीकी पिछड़ेपन और स्थानीय सहभागिता की कमी जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं। सरकार अकेले प्रत्येक विद्यालय की हर आवश्यकता पूरी करे, यह व्यावहारिक रूप से कठिन है। ऐसे में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्या भारती के विस्तार के साथ यह सहयोग एक नया मॉडल विकसित कर सकता है-सरकार आधारभूत संरचना और नियामक सहयोग दे, स्वयंसेवी संगठन शैक्षिक नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी और मूल्याधारित कार्यक्रमों में योगदान करें तथा स्थानीय समाज विद्यालय को अपना संस्थान समझकर उसके विकास में सहभागी बने। विद्या भारती के विस्तार के साथ यदि व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए, जिसमें भारतीय दर्शन के साथ आधुनिक शिक्षाशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, मनोविज्ञान, कौशल शिक्षा और नई मूल्योंजन पद्धतियां शामिल हों, तो यह पूरे देश के लिए अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जैसे क्षेत्रों में विशेष विस्तार की बात भी कही है और वहां राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इन राजनीतिक आरोपों से अलग शिक्षा की दृष्टि से मूल प्रश्न यह है कि संवेदनशील और सामाजिक रूप से विविध क्षेत्रों में विद्यालय नागरिकता-बोध, संवैधानिक कर्तव्य, सामाजिक

समरसता, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय एकता को कितना मजबूत कर सकते हैं। शिक्षा का सर्वोत्तम उत्तर किसी समुदाय के विरुद्ध अविश्वास पैदा करना नहीं, बल्कि हर बच्चे में जिम्मेदार और जागरूक भारतीय नागरिकता का निर्माण करना है। वंदे मातरम, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभावना जैसे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के वक्तव्य ने बहस को राजनीतिक आयाम जरूर दिया है। लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से आवश्यकता ऐसी शिक्षा की है जिसमें राष्ट्रप्रेम स्वाभाविक संस्कार बने, आदेश या भय का विषय नहीं।

पश्चिम बंगाल की यह पहल इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक या प्रेरणा है कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। सरकार, समाज, अधिभावक, शिक्षक, उद्योग, स्वयंसेवी संस्थाएं और पूर्व विद्यार्थी-सभी मिलकर शिक्षा का नया सामाजिक तंत्र बना सकते हैं। यदि विद्या भारती के पास संगठनात्मक अनुभव है, सरकार के पास संसाधन और नीतिगत शक्ति है तथा समाज के पास सहभागिता की क्षमता है, तो इन तीनों का समन्वय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज भारत को ऐसी शिक्षा चाहिए जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई भी; वैज्ञानिक भी हो और संस्कारवान भी; रोजगारपरक भी हो और चरित्रनिर्माणकारी भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसके लिए नीतिगत दिशा दी है। अब आवश्यकता है कि विभिन्न राज्य और सामाजिक संगठन अपने-अपने स्तर पर इसके प्रभावी प्रयोग प्रस्तुत करें। पश्चिम बंगाल में विद्या भारती के एक हजार नए विद्यालयों का लक्ष्य इसी संदर्भ में एक प्रयोगशाला बन सकता है।

शुभेंदु अधिकारी की घोषणा इसलिए बधाई के योग्य है कि इसने शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़ाकर सामाजिक सहभागिता और भारतीय शिक्षा-दृष्टि के विमर्श के केंद्र में ला दिया है। अब असली परीक्षा घोषणा की नहीं, उसके क्रियान्वयन की है। यदि एक वर्ष में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ शिक्षक की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, आधुनिक विज्ञान, तकनीकी दक्षता, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिकता, संवैधानिक चेतना और सामाजिक समरसता को समान महत्व दिया गया, तो बंगाल का यह प्रयोग केवल बंगाल का नहीं रहेगा। यह भारत को यह संदेश दे सकता है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए केवल नई इमारतें नहीं, नई दृष्टि और समाज की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है।

पैर की उंगलियों का आकार बताता है स्वभाव!



अगर किसी व्यक्ति की अंगुठे के बाद की उंगली आकार में ज्यादा लंबी है, तो आप जरूरत से ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं कि सामने वाला आपकी तरफ हमेशा आकर्षित होता है।

पैर की सभी उंगलियों का बराबर होना

अगर आपके पैर की सभी उंगलियां एक ही आकार की हैं, तो आप बहुत सुलझे हुए, स्थिर और विश्वसनीय लोगों में हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और अपने दिमाग से ज्यादा दिल की बात सुनते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। आप ऐसे व्यक्तित्व वाले हैं जो अपनी क्षमताओं की वजह से दूसरों के बीच अलग पहचान बना लेते हैं।

अगर आपके पैरों में छह उंगलियां हैं तो आप

बहुत भाग्यशाली हैं। आप वर्कप्लेस में हमेशा आगे रहते हैं और आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटी है और अपने काम के बलबूते ही अलग पहचान बना सकते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और फैसले लेने में सबसे आगे होते हैं। ये लोग जिस काम को भी शुरू करते हैं उसमें सबसे आगे तक जाते हैं।

पैर का अंगूठा और बगल वाली उंगली बराबर

अगर आपके पैर का अंगूठा और बगल वाली उंगली बराबर आकार की है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको किस्मत से बहुत सी चीजें मिलती हैं और आप कम मेहनत में भी ज्यादा परिणाम हासिल करते हैं।

अगर आपके पैरों की उंगलियां भी ऐसे आकार की हैं तो ये सभी आपके व्यक्तित्व की खूबियां हो सकती हैं।

विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा (अब रायगढ़) जिले के गांगोडे गांव में 11 सितंबर 1895 को एक चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव और माता का नाम रुक्मिणी था। उनकी मां का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। वह भगवद्गीता, महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों से बहुत अधिक प्रभावित थे।

विनोबा भावे का कहना था कि उन्हें गांधी जी में हिमालय की शांति और बंगाल का क्रांतिकारी जोश मिलता है। गांधी जी ने विनोबा भावे की यह कहते हुए प्रशंसा की थी कि वह उनके विचारों को बेहतर ढंग से समझते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1940 में अंग्रेज सरकार की युद्ध नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध, प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए विनोबा भावे को चुना था। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक

विनोबा भावे



उत्तराधिकारी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने वर्ष 1955 में देश में अपने भूदान आंदोलन की शुरुआत ऐसे समय की जब देश में जमीन को लेकर रक्तपात होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी।

30 जनवरी 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद उनके अनुयायी दिशा-निर्देश के लिए विनोबा भावे की ओर देख रहे थे। उन्हें इस आंदोलन को अपार जनसमर्थन मिला तथा जनजागरूकता के साथ ही समाजिक निर्णय में लोगों की भागीदारी बढ़ी। विनोबा भावे का मानना था कि भारतीय समाज के पूर्ण परिवर्तन के लिए 'अहिंसक क्रांति' छेड़ने की आवश्यकता है।

विनोबा ने सलाह दी कि अब देश ने स्वराज हासिल कर लिया है, ऐसे में गांधीवादियों का उद्देश्य एक ऐसे समाज

विनोबा भावे

का निर्माण करना होना चाहिए, जो सर्वोदय के लिए समर्पित हो। तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट छात्र और कुछ गरीब ग्रामीणों ने छापामार गुट बना लिया था। यह गुट अमीर भूमि मालिकों की हत्या करके या उन्हें भगा कर तथा उनकी भूमि आपस में बांटकर जमीन पर ऐसे लोगों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास कर रहा था।

ऐसा भी समय आया जब छापामार गुट ने कई गांवों के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन सरकार की ओर से सेना भेजी गई। दोनों ओर से हिंसा शुरू हो गई। विनोबा भावे ने इस संघर्ष का हल निकालने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में पैदल ही जाने का फैसला किया।

विनोबा भावे अपनी पदयात्रा के

विनोबा भावे

तीसरे दिन तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव पहुंचे, जो कम्युनिस्टों का गढ़ था। वह मुस्लिम प्रार्थना स्थल परिसर में रुकें। जल्द ही गांव के सभी वर्ग के लोग उनसे मिलने आने लगे। उनसे मिलने पहुंचे लोगों में भूमिहीन दलितों के 40 परिवार भी थे। इस समूह ने विनोबा को बताया कि उनके पास कम्युनिस्टों का समर्थन करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे ही उन्हें भूमि दिला सकते हैं।

समूह में शामिल लोगों ने विनोबा से पूछा कि क्या वह सरकार से उन्हें जमीन दिला सकते हैं। विनोबा ने कहा, 'इसके लिए सरकार की क्या जरूरत है, हम स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं।' विनोबा भावे ने बाद में गांव में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने सभा में दलितों की समस्या रखी।

आज का इतिहास

- 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया।
- 1906 महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ किया।
- 1919 अमेरिकी नौसेना ने हॉङ्गरास पर आक्रमण किया।
- 1939 इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1941 अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पॅटगान का निर्माण शुरू हुआ।
- 1951 इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविंक। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे।
- 1961 विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना।
- 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुर्की शहर पर कब्ज़ा किया।
- 1968 एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नाइस में निकट दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 89 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों की मौत।
- 1971 मिश्र में संविधान को अंगीकार किया गया।
- 1973 चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलांदे का सैन्य तख्तापलट।
- 1996 राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित।
- 2001 अमेरिका के वल्ट्‌ड ट्रेड सेंटर व पॅटगान पर आतंकवादी हमले में 6 हजार से अधिक लोग मरे।
- 2003 चीन के विरोध के बावजूद तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश मिले।
- 2005 गाज़ा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा।

- 2006 पेस और डेम की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का युगल ख़िताब जीता।

- 2006 भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी.एन. भगवती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चौथी बार पुनर्निर्वाचित।

- 2006 प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की।

- 2006 स्विट्ज़रलैंड के रोजर फेडरर को लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता।

- 2006 अमेरिकी अंतरिक्ष यान अटलांटिस अंतरिक्ष के साथ जुड़ा।

- 2007 येरूशलम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा।

ब्रिक्स : भारत की मेजबानी में ग्लोबल साउथ की शक्ति का ऐतिहासिक प्रदर्शन

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ की आर्थिक और कूटनीतिक व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है,जहाँ शक्ति का अर्थ केवल सैन्य क्षमता या किसी देश की जीडीपी नहीं रह गया है,बल्कि पूँजी, तकनीक, ऊर्जा,डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर,विदेशी मुद्रा, सप्लाई चेन,बाजार और वैश्विक संस्थाओं पर प्रभाव का संयुक्त परिणाम बन गया है। इसी बदलते वैश्विक समीकरण के बीच भारत 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय बिल्डिंग फॉर रैसिलेन्स इन्वोवेशन, क्षोभापरेक्षण एंड सस्टेनेबिलिटी है और इसका केंद्रीय दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी वैश्विक मंच देना तथा सहयोग को व्यावहारिक परिणामों में बदलना है। मैं यह मानता हूँ कि इस सम्मेलन को केवल एक सामान्य बहुपक्षीय बैठक के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। वर्ष 2026 में ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर रहा है और भारत चौथी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है।भारतीय अध्यक्षता के दौरान 25 से अधिक शहरों में350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय संवाद आयोजित किए जा चुके हैं।राजनीतिक-सुरक्षा,आर्थिक-वित्तीय और सांस्कृतिक-जनसंपर्क,इन तीनों आयामों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।इसलिए 12-13 सितंबर का शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष चले इस व्यापक कूटनीतिक अभियान का निर्णायक राजनीतिक मंच बनने जा रहा है।

साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न स्वाभाविक रूप से जी 7 बनाम ब्रिक्स का है।जी 7 आज भी विकसित औद्योगिक लोकतंत्रों वैश्विक वित्त,उच्च तकनीक और संस्थागत प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली समूह है।दूसरी ओर ब्रिक्स का विस्तार इसे केवल कुछ उभरती

अर्थव्यवस्थाओं के समूह से कहीं अधिक व्यापक मंच बना चुका है।इसलिए भविष्य की दुनियाँ को कौन जीतेगा जी 7 या ब्रिक्स ? जैसे सरल प्रश्न से समझना पर्याप्त नहीं होगा।वास्तविक प्रश्न यह है कि कौन वैश्विक आर्थिक नियमों, व्यापारिक नेटवर्क, तकनीकी मानकों और विकास की प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर पाएगा? यही वह क्षेत्र है जहाँ नई दिल्ली सम्मेलन का महत्व सटीकता से असाधारण हो जाता है।

साथियों ब्रिक्स की सबसे बड़ी शक्ति उसका ग्लोबल साउथ डिमेंशन है। भारत लगातार यह रेखांकित करता रहा है कि विकासशील देशों की आवाज वैश्विक शासन संस्थाओं में उनकी वास्तविक आर्थिक और जनसंख्या शक्ति के अनुरूप दिखाई देनी चाहिए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आर्थिक सहयोग के साथ- साथ तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार स्टार्टअप पर्यावरण साइबर सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों को महत्व दिया गया है। अगस्त में ब्रिक्स कम्युनिकेशन्स मिनिस्टर्स मीटिंग में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और भविष्य की नेटवर्क तकनीक, साइबर सुरक्षा, डिजिटल रिकलिंग, स्टार्टअप तथा नवाचार को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया था।यहीं भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ब्रिक्स को किसी पश्चिम- विरोधी सैन्य या राजनीतिक गठबंधन के रूप में स्थापित करने के बजाय बहुध्रुवीय और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के मंच के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यह दृष्टिकोण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से भी जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली के लिए रूस के साथ ऊर्जा और रणनीतिक संबंध, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार एवं तकनीकी साझेदारी और ग्लोबल साउथ के साथ विकासात्मक जुड़ाव, इन सभी को एक साथ संतुलित करना आवश्यक है। यही भारत की सटीकता से कूटनीतिक चुनौती भी है और अवसर भी।

सत्य निकेतन के बाद सवाल– जिम्मेदार कौन?

पुष्पेंद्र चौहान

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इन इमारतों के गिरने पर जान गंवाने वालों के जीवन की क्या कोई कीमत नहीं है। एक के बाद एक ऐसे हादसे होते चले जा रहे हैं और हर बार जांच रिपोर्ट और चर्च अफसरों पर विभागीय कार्रवाई के बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। सवाल यह भी कि क्या इस बार हालात सुधारने के लिए सरकार गंभीर है। दिल्ली के ललितா पार्क में 2010 में इस तरह के हादसे में 71 लोगों की जान गई, ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में नौ लोगों की मौत हुई, कोचिंग सेंटर में आग लगने और पानी भरने से भी मौतें हुईं। तब भी तमाम जांचें व सरकारी दावे हुए, लेकिन साल दर साल हादसे और अवैध निर्माण बढ़ते ही रहे। जिन पर जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्या अधिकारियों पर इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं थी? कानूनी दायरे में नहीं आने का ही नतीजा है कि सरकारी तंत्र आखें मूंदे रहता है और अवैध तरीके से इमारतें बनती जा रही हैं। अवैध निर्माण पर नजर रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की तो है, पर बिजली, पानी-सीवर का कनेक्शन देने वाले विभाग और पुलिस क्या करती है? क्या यह देखा इन विभागों का काम नहीं है कि जो संसाधन 10 लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए, अगर उनका इस्तेमाल 100 लोग करने लगेंगे, तो व्यवस्था पर कितना बोझ बढ़ेगा। दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भ्रष्टाचार का गठजोड़ देश के अन्य हिस्सों से अलग है। न केने के लिए ख़त की ज़रूरत इतनी ज्यादा है कि इसके लिए हर कानून को ताक पर रख दिया जा रहा है। यह गठजोड़ इलाके में निर्माण करवाने वाले ठेकेदार बताते हैं, जो पहले मकान मालिक को तैयार करते हैं, फिर पुलिस-प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को उनका हिस्सा पहुंचाकर बेफ़िक्र होकर निर्माण शुरू कर देते हैं। हर अवैध निर्माण की कीमत तय है। स्थानीय नेता इस गठजोड़ को संरक्षण देते हैं। हर जगह यही सिंडिकेट काम कर रहा है। कई जगहों पर तो नेताओं और उनके लोगों ने

ही किराये के लिए कई-कई मकान बनवा रखे हैं। ठेकेदार कहने के लिए निर्माण करवाते हैं। इनका मुख्य काम बिचौलिये का होता है। बेहतर भविष्य बनाने के लिए अलग-अलग हिस्सों से युवा नौकरी करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से लेकर पढ़ाई करने तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी का रुख करते हैं। ऐसे में कच्ची-पक्की, दोनों तरह की आवासीय कॉलोनियों धीरे-धीरे स्टूडेंट्स का हब बनती जा रही हैं। रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक पीजी खुलते जा रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में किराये का कारोबार बहुत बड़ा है। यहीं से अवैध निर्माण की बुनियाद तैयार होती है। जहां तीन मंजिलों की अनुमति है, वहां पांच मंजिला इमारतें बना दी जा रही हैं। इमारत के पिलर कितने मजबूत हैं, पिलर हैं भी या नहीं, कोई जांचने-परखने वाला नहीं है। इस तरह के हादसों में संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो वे भी आखें मूंदे रहते हैं। कई बार लालच में आकर, तो कई बार राजनीतिक वजहों से। समस्या केवल भ्रष्टाचार की नहीं है। हमारी शहरी नियोजन व्यवस्था भी इसका मुख्य कारण है। बड़े-बड़े निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में हॉस्टल नहीं हैं। नोएडा का ही उदाहरण ले लें। नौकरी के लिए यहां आने वाले निम्न आय वर्ग के लोग कहां रहेंगे, इस पर कोई योजना नहीं है। नतीजतन, डूब क्षेत्र में हिंडन और यमुना के किनारों पर बड़ी संख्या में कच्ची कॉलोनियां बसा दी गईं। इसमें भी भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने ही काम किया। गांवों में रहने वाले स्थानीय लोग धीरे-धीरे अपने पुश्तैनी घर छोड़कर अच्छे रिहायशी इलाकों में शिफ्ट हो गए और गांव में अधिकांश किरायेदार ही बचे। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले, जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो। चरणबद्ध तरीके से इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की एक दीर्घकालिक परियोजना पर काम और पुरानी व जरूर कॉलोनियों का पुनर्विकास हो। नए निर्माण की सूचना निगम या संबंधित निगम को देना अनिवार्य किया जाए। पर्याप्त संख्या में हॉस्टल बनाए जाएं।



साथियों सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिन्पिंग की संभावित उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार चीनी पक्ष ने उनकी संभावित यात्रा के लिए सुरक्षा और प्रोटोकॉल संबंधी तैयारियाँ शुरू की हैं, लेकिन 8 सितंबर तक उनकी यात्रा को लेकर औपचारिक अंतिम कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं था। यदि शी जिन्पिंग नई दिल्ली आते हैं, तो यह 2019 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी और ब्रिक्स मंच पर भारत-चीन संबंधों को नई दिशा देने का अवसर भी बन सकती है। मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि चीनी राष्ट्रपति बहुत बड़े डेलिगेशन के साथ भारत आने की सटीकता से उम्मीद है।

साथियों रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को लेकर स्थिति कहीं अधिक स्पष्ट है।भारतीय पीएम ने ने 31अगस्त को पुतिन से मुलाकात के दौरान उन्हें 12–13 सितंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत आने का स्वागत करने की बात कही थी।दोनों नेताओं ने ब्रिक्स के तहत सहयोग सहित राजनीतिक, आर्थिक,ऊर्जा,अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इससे स्पष्ट है कि नई दिल्ली सम्मेलन भारत-रूस संबंधों और व्यापक ग्लोबल साउथ डिक्लोमेसी के लिए भी महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है।

साथियों, ब्रिक्स का दूसरा बड़ा आयाम वित्तीय और

राजकुमार सिंह

अंतिम परिणति तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ‘जेन-जी’ के जंतर-मंतर प्रयोग ने चुनावी सिलेबस बदल दिया है। इसका दबाव राजनीतिक दलों-नेताओं पर दिख रहा है। नौकरी देने के अधूरे वायदों के अलावा याद नहीं पड़ता कि देश में कभी शिक्षा, परीक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को शासकीय तो दूर, चुनावी एजेंडे में भी प्राथमिकता मिली हो। युवाओं की बढ़ती आबादी के मद्देनजर ‘युवा भारत’ के नारे सुने जाते रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर शिक्षा और उपयुक्त रोजगार देकर देश के विकास को मुख्यधारा का इंजन बनाने की योजना सामने नहीं आई।

हां, देश और प्रदेशों में अंतर्हीन पेपर लीक और भर्ती घोटालों की तलवार अक्सर युवाओं के भविष्य पर लटक नीजर आई। कटु सत्य यह भी कि देश का भविष्य कहे जानेवाले युवाओं के भविष्य से इस खिलवाड़ पर छात्रों-युवाओं के नाम पर बने राजनीतिक दलों के संगठन भी मूकदर्शक बने रहे।

कांक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का ऑनलाइन जन्म सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की एक दिष्णगी के चलते हुआ, लेकिन जंतर-मंतर पर और उसके बाद उसे मिल रहा समर्थन छात्रों और युवाओं के मुद्दों की अनवरत अनदेखी का परिणाम भी है। बेशक जंतर-मंतर पर और उसके बाद भी सीजेपी से कुछ राजनीतिक दलों-नेताओं का मेलजोल नजर आ रहा है, लेकिन इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि देश के सभी दलों के शासनवाले राज्यों में पेपर लीक और भर्ती घोटाले होते रहे हैं। इसीलिए अब छात्र और युवा, जाति-धर्म-क्षेत्र-राजनीतिक रूझान की सीमाएं लांग कर शिक्षा, परीक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर कमोबेश सभी राज्यों में सड़क पर उतर रहे हैं। जंतर-मंतर के बाद झारखंड में भी छात्रों-युवाओं का सफल आंदोलन और उसका राजनीतिकरण दिखा, तो अब स्कूली शिक्षा की बदहाली के विरुद्ध



राज्य-दर-राज्य ‘जेन-अल्फा’ के भी सड़क पर उतरने की खबरें हैं। जिन छात्र-छात्राओं को स्कूल-कॉलेज की कक्षाओं में होना चाहिए, उनका सड़क पर उतरना देश-समाज की सकारात्मक तस्वीर पेश नहीं करता, पर उन्हें व्यवस्था ने ही मजबूर किया है। बिना भवन और पर्याप्त शिक्षकों के स्कूल चलने की शिकायतें देशभर में आम हैं, पर उनका निराकरण करने के बजाय बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। व्यवस्था की दृष्टि से यह प्रतिबंध उचित लग सकता है, पर स्कूल की खामियां देखने-दिखाने की अनुमति बिना कौन-सा प्रशासन देगा? कुछ राज्यों से स्कूली बच्चों के पैदल जिला मुख्यालय पहुंच कर स्कूल की बदइंतजामी प्रशासन को बताने की खबरें भी यही बताती हैं कि निगरानी जिनकी जिम्मेदारी है,

वे अपना काम नहीं कर रहे। हमारे यहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। स्कूल शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद हैं। बुनियाद ही बदहाल है तो उस पर बननेवाली इमारत के हाल की कल्पना ही की जा सकती है।

कुछ छात्र मेहनत और किस्मत से प्रतियोगी परीक्षाओं की दहलीज तक पहुंच जाते हैं तो पेपर लीक और भर्ती घोटाले सपने चकनाचूर करने का चक्रव्यूह रचे तैयार मिलते हैं। पेपर लीक के लिए अक्सर

हिस्सों में लैंडस्केपिंग, फूलों की सजावट, मुरलस और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य किए गए हैं।यह केवल सजावट नहीं, बल्कि भारत की सांपट पावर और आयोजन क्षमता का प्रदर्शन भी है। 2023 के जी 20 के बाद दिल्ली एक बार फिर दुनियाँ के सामने स्वयं को बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी करने में सक्षम राजधानी के रूप में प्रस्तुत कर रही है।आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 11 सितंबर को दिल्ली के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के दिल्ली स्थित कार्यालयों के लिए भी 11 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है,जबकि 12 और 13 सितंबर सप्ताहांत हैं। इन फैसलों के पीछे सम्मेलन से जुड़ी सुरक्षा, यातायात और लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुचारू रखना प्रमुख कारण है।

साथियों, दिल्ली पुलिस ने भी 11 से 13 सितंबर के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की है।आधिकारिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर इस अवधि के लिए अलग ब्रिक्स ट्रैफिक एडवाइज़री उपलब्ध है। सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के कारण प्रमुख मार्गों पर डाइवर्शन और ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अधिकृत स्थानों पर ही पार्किंग करने और किसी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। इस स्तर की तैयारी बताती है कि सम्मेलन केवल भारत मंडपम तक सीमित आयोजन नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक बड़ा लॉजिस्टीकल एक्ससाइज है।

साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है,भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था का सहभागी नहीं, बल्कि उसके पुनर्संतुलन में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देना चाहता है, लेकिन साथ ही पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से अपने संबंध भी बनाए रखना चाहता है।

बांग्लादेश को दुश्मन खेमे में जाने से भारत ने चला बड़ा दांव!

नीरज कुमार दुबे

बांग्लादेश को दुश्मन खेमे में जाने से रोकने के लिए भारत तेजी से सक्रिय हो गया है। ढाका के संभावित रूप से सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान से जुड़े ‘मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट’ जैसे सामूहिक सुरक्षा ढांचे में शामिल होने की खबरों ने नई दिल्ली की रणनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत ने इस मुद्दे पर तीव्र बैकचैनल कूटनीति शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर बांग्लादेश की असली मंशा क्या है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच वर्षों से बंद पड़ी यात्री रेल सेवाओं को फिर शुरू करने की कवायद भी तेज हो गई है।

रिपोर्टों के मुताबिक, बांग्लादेश मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। यह एक ऐसा पारस्परिक रक्षा ढांचा बताया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान शामिल हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बदले राजनीतिक माहौल में ढाका अपनी विदेश नीति को अधिक विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेशी रणनीतिक हलकों में संभावित सदस्यता को तुर्किये की सैन्य तकनीक, सऊदी अरब की आर्थिक सहायता और पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग हासिल करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसे व्यापक रूप से ‘मुस्लिम फैमिली’ के ढांचे में कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है।

लेकिन नई दिल्ली की नजर से तस्वीर कहीं अधिक गंभीर है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी सामूहिक रक्षा ढांचे का विस्तार सीधे उसके पूर्वी मोर्चे तक हो सकता है। यदि बांग्लादेश औपचारिक रूप से ऐसे किसी सैन्य समझौते में शामिल होता है, तो भारत के आसपास एक नए सामरिक समीकरण का निर्माण हो सकता है। बंगाल की खाड़ी तक फैला सामूहिक सुरक्षा ढांचा भारत की रणनीतिक गणनाओं को बदल सकता है।

हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऐसे में पूर्वी सीमा



पर किसी नए सुरक्षा गठबंधन की मौजूदगी नई दिल्ली के लिए साधारण कूटनीतिक घटनाक्रम नहीं होगी। भारत को अपने पड़ोस को केवल द्विपक्षीय रिश्तों के नजदिये से नहीं, बल्कि एक संभावित मल्टी-फ्रंट सिक्वोरिटी थिएटर के रूप में देखना पड़ सकता है। यही वजह है कि भारतीय बैकचैनल यह टटोलने में जुटे हैं कि ढाका वास्तव में कोई बाध्यकारी सैन्य प्रतिबद्धता चाहता है या फिर इस तरह की संभावनाओं का इस्तेमाल भारत समेत अन्य शक्तियों से कूटनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहा है।

इसी रणनीतिक तनाव के बीच भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक सकारात्मक संकेत भी उभर रहा है। दोनों देश बंद पड़ी यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ढाका में आज से दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों की बैठक शुरू हुई है, जिसमें मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस को दोबारा पटरी पर लाने पर चर्चा हो रही है।

बांग्लादेश रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक (ऑपरेशंस) मोहम्मद नजमुल इस्लाम के अनुसार, दोनों देशों के बीच यात्री रेल संपर्क अगस्त 2024 के बाद से बंद है, जबकि मालगाड़ियां बिना किसी बाधा के लगातार चलती रही हैं। मैत्री एक्सप्रेस ढाका कैटोनमेंट और कोलकाता के बीच चलती थी, बंधन एक्सप्रेस खुलना और कोलकाता को जोड़ती थी, जबकि मिताली एक्सप्रेस ढाका कैटोनमेंट से न्यू जलपाईगुड़ी तक संचालित होती थी।

इन सेवाओं को जुलाई 2024 में आधिकारिक रूप से निलंबित किया गया था। इसके बाद देशव्यापी अशांति, शेख हसीना सरकार के पतन और 5 अगस्त 2024 को

उनके भारत जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम व्यवस्था के दौरान शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और उनके प्रत्यर्पण की मांग जैसे मुद्दों ने संबंधों में खटास पैदा की।

हालाँकि, बांग्लादेश में 22 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव के बाद एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनी और अब दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्तों की बहाली की ज़रूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है।

वर्तमान अंतर-सरकारी रेलवे बैठक यानी आईजीआरएम में केवल ट्रेनों को शुरू करने पर ही नहीं, बल्कि वित्तीय हिसाब-किताब, सीमा पार ट्रेन परिचालन, वार्षिक लेखा संतुलन, परिचालन क्षमता, रोलिंग स्टॉक और रेलवे ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश की योजना राजशाही से कोलकाता के लिए एक नई ट्रेन शुरू करने की भी है। साथ ही, मैत्री एक्सप्रेस को जमुना ब्रिज के बजाय पद्मा ब्रिज के रास्ते चलाने का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है।

भारत द्वारा 27 जून से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर शुरू किए जाने के बाद आम लोगों के बीच भी रेल सेवाओं की बहाली की मांग तेज हुई है। भारतीय उच्चायुक्त ने भी दोनों देशों के बीच ‘पीपुल-टू-पीपुल रिलेशन’ को बेहद अहम बताया है। दरअसल, यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक तरफ भारत बांग्लादेश के संभावित नए सैन्य समीकरणों को लेकर सतर्क है, दूसरी तरफ वह रेल, वीजा, व्यापार और जनसंपर्क के जरिए रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली समझौती है कि अगर ढाका रणनीतिक रूप से दूर गया, तो भारत की पूर्वी सुरक्षा चुनौती स्थायी रूप से बदल सकती है। इसलिए कूटनीति अब सिर्फ दोस्ती बचाने की नहीं, बल्कि बांग्लादेश को किसी संभावित दुश्मन खेमे की ओर झुकने से रोकने की रणनीतिक लड़ाई बन चुकी है।

जर्मनी के सबसे खतरनाक आदमी को मिलने वाली है सत्ता?

अभिनय आकाश

किस तरह एक विधानसभा चुनाव ने जर्मनी के भीतर भौगोलिक और वैचारिक दरार को इतना पुछा कर दिया है कि इसे देश के आधुनिक दौर का सबसे खतरनाक पल माना जा रहा है और क्यों जर्मनी के एक असंबली रिजल्ट से पुतिन बहुत खुश होंगे। इस बरस 3 अक्टूबर को जर्मनी अपना 36वां टाक डे ‘डचिन आइनाइट्ट मनाएगा यानी एकीकरण दिवस’। 3 अक्टूबर 1990 को दो हिस्सों में बटे जर्मनी के एक होने की सालगिरह। उसी दिन जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जीडीआर आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। लेकिन जमीन पर जर्मनी के दो हिस्सों का बंटवारा कायम रहा और इस की एक परिणति हुई इस 6 सितंबर को बैलेट पेपर के जरिए। जर्मनी के 16 राज्यों में से एक आकार में बम मुश्किल भारत के मणिपुर या मिजोरम जितना बड़ा करीब सवा 5 लाख की आबादी। एएफडी यानी अल्टरनेटिव फॉर डेवैंड। 2026 में 39 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी 2021 के चुनाव में इसे 23 सीटें मिली थी। सीडीयू यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। जर्मनी में अभी केंद्र में जो सरकार है उसका नेतृत्व इसी से पास है और सेक्सनी अनहल्ट में राज्य सरकार को भी यही इसी यही पार्टी लीड कर रही थी। ताजा चुनाव में उसे मिली 15 सीटें। पिछले चुनाव में मिली थी 40 सीटें। डी लंकर यानी लेफ्ट पार्टी को अभी मिली आठ, 2021 में 12 सीट, एस्पपीडी यानी सोशल डेमोक्रेट्स को 2026 में आठ सीट, 2021 में नौ सीट, ग्रीस को अभी आठ, 2021 में छह सीट, बीएसडब्ल्यू यानी ज़ारा वागन क्लिष्ट पार्टी को पांच सीट। 35 साल के उलरिष जिंगमुंड 2016 से सेक्सनी अनहल्ट की विधानसभा के सदस्य है। सोशल मीडिया पर अच्छी

पकड़ है। माना जाता है कि उनकी जीत में जेन-जी के समर्थन का बड़ा हाथ है। वह अपनी पार्टी के कट्टरपंथी नेताओ के मुकाबले ज्यादा नरम माने जाते है। जिंगमुंड ने कहा कि लोगों ने साफ कर दिया है कि वे राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। एएफडी का जोर अवैध प्रवास रोकने, प्रवासियों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती और बड़ा संख्या में लोगों को वापस भेजने की नीति पर है। चुनाव में यह बहस का मुद्दा बना। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ल्स और उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स (सीडीयू) के लिए बड़ा झटका है, जिसे महज 17.2ब वोट मिले है। सीडीयू 24 साल से इस प्रांत में सत्ता में थी। एएफडी की जीत से पूरे यूरोप में खलबली मची है। जर्मनी में जिन वजहों से पार्टी को जीत मिली, वैसे मुद्दे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन में भी उठाए जाते रहे है। अगले साल फ्रांस, इटली, स्पेन में चुनाव है, जहां धुर-दक्षिणपंथी नेता मजबूत हो रहे है। ये एएफडी के तरीकों का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकते है। पर इन नेताओं का सत्ता में आना उदारवादी लोकतंत्र के लिए बुरी खबर है। रूस ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। फ्रांस ने इसे पूरे यूरोप के लिए गंभीर समय बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नतीजे की तस्वीर साझा की। एक प्रतिष्ठित जर्मन पत्रिका है डे एंग पिंगल। 14–15 अगस्त को आई मेगज़ीन की कवर स्टोरी पर उलश की तस्वीर थी। शीर्षक था जर्मनी में सबसे खतरनाक इंसान ना उलरिष और ना उनके समर्थकों को इस विशेषण से कोई फर्क पड़ा बल्कि वो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह सराते दिखे। इलेक्शन कैंपेन से यह तस्वीर आई कि किस तरह सपोर्टेड टीशर्ट पर शपीगल कवर स्टोरी की फोटो छपाकर घूम रहे थे। यहां तक कि शपीगल के उस एडिशन पर उलश से दस्तखत की फरमाइश भी हो रही थी। क्या है परिचय उलश का ?

काशीटोला में ‘हर घर जल’ से बदली तस्वीर, नल से पहुंचा स्वच्छ पेयजल तो आसान हुई जिंदगी

काशीटोला में ‘हर घर जल’ से बदली तस्वीर, नल से पहुंचा स्वच्छ पेयजल तो आसान हुई जिंदगी

एमसीबी। जल जीवन मिशन ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के दूरस्थ ग्राम काशीटोला में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। ग्राम पंचायत बहारसी के अंतर्गत आने वाले काशीटोला में ‘हर घर जल’ योजना के तहत घर-घर नल कनेक्शन पहुंचने से वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या का समाधान हुआ है। लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव ने स्वच्छ पेयजल की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

पहले पानी के लिए करना पड़ता था इंतजार

काशीटोला में पहले ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कुएं, हैंडपंप अथवा दूरस्थ जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मी के मौसम में जल स्रोत सूखने से समस्या



और गंभीर हो जाती थी। पानी की कमी के साथ उसकी गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों को परेशानी होती थी। इसका असर स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर भी पड़ता था। गांव में नल-जल सुविधा नहीं होने के कारण महिलाओं को विशेष रूप से पानी लाने में काफी समय लगाना पड़ता था। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। **जल जीवन**

मिशन ने शुरू किया बदलाव

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहारसी को चयनित कर घर-घर नल कनेक्शन पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और ग्रामीणों की सहभागिता से पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से पूरा किया गया। जल स्रोतों के संरक्षण एवं सुधार के साथ ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया तथा जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी शुरू हुई। आज काशीटोला के 100 प्रतिशत घरों में जल प्रमाणीकरण हो चुका है और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है।

पानी पहुंचा तो बदली जिंदगी

नल से घर तक पानी पहुंचने के बाद ग्रामीणों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। जलजनित बीमारियों में कमी आई है और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं का पानी लाने में लगने वाला समय बच रहा है,

जिससे उन्हें घरेलू कार्यों के साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी अधिक समय मिल रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है।

ग्रामीणों की भागीदारी बनी सफलता की ताकत

काशीटोला की इस उपलब्धि के पीछे ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। ग्रामीणों ने योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने के साथ जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाई। यही सामुदायिक सहभागिता योजना को स्थायी बनाने में मददगार बनी है। आज काशीटोला केवल स्वच्छ पेयजल से जुड़ा गांव नहीं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता और सरकारी योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रेरक उदाहरण बन चुका है। ‘हर घर जल’ का सपना यहां साकार होकर यह संदेश दे रहा है कि जनभागीदारी के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन गांवों की तस्वीर और ग्रामीणों की जिंदगी दोनों बदल सकता है।

अधूरे पुल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत

संज्ञान, मुख्य सचिव को

नोटिस भेजकर मांगा जवाब

गरियाबंद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक इलाके में स्कूली बच्चों के अधूरे बने पुल से नदी पार करने के खतरों की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लगभग छह साल से बन रहा यह पुल अभी भी अधूरा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (ह्राइट्स) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के मैनपुर ब्लॉक इलाके में खंभाथा और आस-पास की बस्तियों के दर्जनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए पैरों नदी पार करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें एक अधूरे पुल से जुड़ी संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए



मजबूर होना पड़ता है। बताया गया है कि मॉनसून के दौरान यह उथली नदी तेज़ बहाव वाली नदी में बदल जाती है।

आयोग ने पाया है कि अगर मीडिया रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए, आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर इस मामले पर

विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

3 सितंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार, मैनपुर ब्लॉक में देहारागुड़ा और खंभाथा के बीच लगभग 300 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पिछले छह साल से चल रहा है। अधिकारियों ने लगभग एक साल पहले ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि यह पुल छह महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।

यूरिया चोरी के आरोपियों का ग्रामीणों ने निकाला जुलूस

गरियाबंद। जिले के अंतिम छोर और ओडिशा सीमा से लगे मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गौरगांव के आश्रित गांव झोलाराव में चोरी की एक घटना के बाद ग्रामीणों की कार्रवाई चर्चा में है। यहां यूरिया खाद चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले करने के बजाय उनके कंधों पर यूरिया की बोरियां रस्सी से बांधकर गांव में जुलूस निकाला। इस दौरान ढोल-नगाड़े बजाए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, गांव के एक किसान के घर से यूरिया खाद की दो बोरियां चोरी हो गई थीं। चोरी का आरोप गांव के ही प्रभु और कृष्णा नामक दो युवकों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कथित तौर पर खाद की बोरियां लेकर उसे ठिकाने लगाने और बेचने की तैयारी में थे।

इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को यूरिया की बोरियों के साथ पकड़ लिया। पृष्ठताछ के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पुलिस के सुपुर्द करने के बजाय मौके पर ही अपने स्तर पर कार्रवाई करने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने दोनों युवकों के



कंधों पर वही यूरिया की बोरियां रस्सी से बांध दीं, जिन्हें चोरी का बताया जा रहा है। इसके बाद ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों को पूरे गांव की बस्ती में पैदल घुमाया गया। घटना को देखने के लिए गांव के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी घरों से बाहर निकल आए।

इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद झोलाराव गांव की यह घटना आसपास के क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बन गई है।

घटना के बाद ग्रामीणों के बीच इस कार्रवाई को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे चोरी की

घटनाओं के खिलाफ ग्रामीणों की सख्ती बता रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप होने की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई कराना ही उचित प्रक्रिया है।

फिलहाल प्रभु और कृष्णा पर लगाए गए चोरी के आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं, ग्रामीणों द्वारा दोनों युवकों को सार्वजनिक रूप से घुमाए जाने के मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। अब पुलिस जांच में चोरी की घटना और पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर नजर बनी हुई है।

तीन मवेशी तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे

धमतरी। धमतरी जिले में गौवंश के अवैध परिवहन और पशु क़रूरता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 मवेशियों को बरामद किया है, जिन्हें पिकअप वाहन में दूस्-दुंसकर भरा गया था। साथ ही तस्करी में शामिल तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला सिहावा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में मवेशियों को क़रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने नगरी-सिहावा मुख्य मार्ग पर देवपुर चौक के पास घेराबंदी की और संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक छत-05-, 4503 को



रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन में 4 गौवंश मवेशी क़रूरतापूर्वक ले जाते हुए पाए गए। पुलिस ने सभी मवेशियों को मुक्त कराया और मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में तानसिंह साहू, भोजराम यादव और करणसिंह

यादव शामिल हैं। मामले में सिहावा थाने में अपराध क्रमांक 71/26 दर्ज कर पशु क़रूरता निवारण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 और 11 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब अवैध पशु परिवहन और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

एसईसीएल की जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

1963-64 में अधिग्रहित जमीन का अब तक नहीं मिला मुआवज़ा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा। 25 सितंबर 2026 को प्रस्तावित रश्मिष्ठर की पर्यावरणीय जनसुनवाई से पहले भिलाई खुर्द सहित आसपास के प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने विरोध जताया है।

पूर्व में ग्रामीणों के विरोध के चलते जनसुनवाई स्थगित की गई



थी। अब दोबारा तारीख तय होने से भू-विस्थापित ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बैठक कर अपनी लंबित मांगों को लेकर

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 1963-64 में अधिग्रहित जमीन के एवज में लंबित मुआवजा और रोजगार देने की

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

पुलिस हिरासत में युवक की मौत का आरोप, जांच हेतु पहुंचे मजिस्ट्रेट

जांजगीर चांपा। चांपा थाना में युवक की कथित मौत का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। परिजनों का कहना है, चांपा पुलिस ने बुधवार को उनके मेहंदी पारा घर पर रेंड किया और अवैध शराब बिक्री का आरोप लगाते हुए उनके लड़के को पकड़कर ले गई। बाद में पुलिस ने उनको बताया कि उनके बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई है।%० युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चांपा थाने पर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके लड़के को थाने में जमकर पीटा गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। परिजन अब चाहते हैं कि मामले की न्यायिक जांच हो और जो भी पुलिसवाले दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। परिजनों के गंभीर शिकायत पर एसपी विजय कुमार पांडेय ने तत्काल एक आरक्षक को निर्लंबित कर दिया है। एडिशनल एसपी का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी।

खेत में आराम फरमाते नजर आया तेंदुआ, देखने पहुंचे ग्रामीण

कवर्धा। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पर स्थित जैतपुरी गांव में धान के खेत में तेंदुआ अपना डेरा जमाया हुआ है। खेत में तेंदुए के घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और किसान अपने खेत में काम करने नहीं जा पा रहे हैं। सुबह जब ग्रामीण अपने खेत की ओर गए तो वहां उन्हें तेंदुआ आराम करते नजर आया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैली। पूरा गांव तेंदुआ को देखने खेत के आसपास इकट्ठा हो गया। ग्रामीणों का दावा है कि तेंदुए ने बीती रात गांव में घूमभूम कर बकरियों का शिकार किया। वन विभाग को सूचना दी, सूचना के बाद तत्कालीन कवर्धा रेंज अधिकारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाने पुलिस को भी बुलाया। पुलिस लोगों को तेंदुआ से दूर रखने का प्रयास कर रही है। वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी विशेषज्ञों को रायपुर से बुलाया गया है। वन विभाग तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए ट्रैकुलाइज करने की तैयारी में जुटा है। विभाग के अनुसार गन को मौके तक पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगा।

ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो देखना होगा वीडियो

कोरबा। सड़क हादसों पर लगाम लगाने और चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य शुरुआत की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान ही ट्रैफिक नियमों से जुड़ा एक विशेष वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके बाद ही लाइसेंस की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। वीडियो में संकेतों और नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क पर वाहन चलाने से पहले ही हर नागरिक को यातायात के बुनियादी उसूलों से पूरी तरह अवगत कराना है। नशे में वाहन चलाने के नुकसान, ट्रैफिक सिग्नलों के अर्थ, सड़क पर ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, और यातायात नियमों के पालन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारीयों विस्तार से शामिल की गई हैं। वीडियो देखने के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी मिलेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को सौगात

बिलासपुर। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। बैठक में रेल मंत्रालय की 3 महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ है। इन परियोजनाओं को 2029 से साल 2030 तक पूरा करने की योजना है।इस परियोजना में महत्वपूर्ण रूप से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजना पहली कटनीडूणेंड्रा रोड चौथी लाइन और दूसरी बिलासपुर (उसलापुर) – पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लंबाई 288 किलोमीटर तथा कुल लागत 4,254 करोड़ है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग की क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। साथ ही ट्रेनों की मोबिलिटी और परिचालन में सुधार और यात्री एवं माल परिवहन को अधिक सुगम, तेज और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को सौगात मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं का लाभ कई जिलों को मिलेगा।

धुरबेड़ा बालक आश्रम पहुंचकर अधिकारी ने परखी व्यवस्थाएं

नारायणपुर। जिले के अंदरूनी एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचालित आश्रम-छात्रावासों में बच्चों को मिल रही सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानने के लिए कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अंत्यावसायी अधिकारी ए.आर. बेलसारिया ने ओरछा विकासखंड के दुर्गम आंचल में बसे धुरबेड़ा स्थित बालक आश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया। आश्रम पहुंचने पर उन्होंने परिसर का भ्रमण कर वहां बच्चों के रहने और अध्ययन के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तथा बच्चों की दिनचर्या से जुड़ी जानकारी भी ली। इस दौरान बच्चों के बीच पहुंचकर अधिकारी ने उनसे उनकी पढ़ाई और आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बातचीत की। बच्चों से उनकी ज़रूरतों और किसी तरह की परेशानी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। चीजों में सुधार की आवश्यकता थी।

कस्तूरबा आवासीय परिसर की बजाए सड़क पार दूसरे भवन में बनाए कमरे

गरियाबंद। देवभोग स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्राओं को आवासीय सुविधा दिलाने परिसर में 6 कमरे बनाने थे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने 300 मीटर दूरी पर दूसरे भवन में 9 कमरे बनवा दिए। अब स्कूल प्रबंध समिति छात्राओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए जांच की मांग कर रही है।

दरअसल, देवभोग और मैनपुर आवासीय कस्तूरबा विद्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आवासीय अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए केंद्र ने 48- 48 लाख के भवनों की मंजूरी 2024 में दी थी, जिसे प्रदेश कार्यालय द्वारा हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बनाकर निर्माण की जिम्मेदारी दे दी। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने विद्यालय की सुविधाओं को नजर अंदाज करते हुए अपने ढंग से भवन का नया ड्राइंग डिजाइन पास करवा लिया, और उसके बाद



भवन निर्माण में मनमानी कर दी। निर्माण पूरा होने के बाद भवन का हेंडओवर लेने हाउसिंग बोर्ड और ठेका कंपनी ने तरह-तरह के दबाव बनाए। मैनपुर विद्यालय की अधीक्षिका ने हेंडओवर ले तो लिया, लेकिन हेंडओवर लेटर में कमियों का जिक्र कर निर्माण एजेंसी की न केवल पोल खोल दी, बल्कि विभाग के उच्च अधिकारियों को भी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। वहीं नए भवन के अनुपयोगी होने से आवासीय विद्यालय के छात्र और पालकों में भी जम कर आक्रोश देखा जा है।

जानकारी के अनुसार, छह कमरों वाले भवन को कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के कैंपस में बनाया जाना था, उद्देश्य था कि वर्तमान भवन में छात्राओं की बढ़ते संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कक्ष में उन्हें रहने की सुविधा मिले। भवन निर्माण के लिए स्कूल प्रबंधन ने पर्याप्त जगह भी हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदारों को दिखाया।लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने ड्राइंग में परिवर्तन कर दिया। लागत में 4 लाख की कमी भी कर दी, और उसे कैंपस से 300 मीटर दूर विद्यालय के शैक्षणिक भवन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बनवा दिया। डिजाइन में 13 कमरे बनाए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने 9 कमरे बनाए। जिस भवन में निर्माण किया गया, वहां पहले से कॉलम भी खड़े थे, जिस पर लैफिंग कर नया भवन बनाया गया। समिति अध्यक्ष सुन्दर सिंह एवं पालकों ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड विभाग

को जो बंदरबांट करना था किए, पर छात्राओं की सुविधाओं के साथ समझौता नहीं करना था। नया भवन 300 मीटर दूर है, जहां छात्राओं को आवासीय सुविधा दे पाना संभव नहीं है। पालकों ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए या दूर स्थित अतिरिक्त भवन में रहने नया सेटअप की मंजूरी दिया जाए, ताकि छात्राओं सुरक्षित रहकर अध्ययन कर सके। गरियाबंद डीएमसी शिवेश शुक्ला का कहना है कि भवन की मंजूरी से लेकर निर्माण की मॉनिटरिंग तक प्रदेश कार्यालय से हुई। हेंडओवर की बारी आई तो अधीक्षिका ने मार्गदर्शन मांगा, चूँकि मौके पर वही रहती हैं, इसलिए जो वस्तुस्थिति है उसे लिख हेंडओवर लेने कहा गया। इस पत्र से जानकारी मिली कि यहां 13 के बजाए 9 कमरे हैं, और संचालन के अन्य व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं।

धर्मातरित महिला के शव दफनाने को लेकर बवाल

परिजन और ग्रामीण हुए आमने-सामने, पुलिस ने संभाला मोर्चा

धमतरी। जिले के नगरी वनांचल में धर्मातरित महिला के शव को दफनाने को लेकर घंटों विवाद की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों की मांग पर जब परिवार ने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई, तब ग्रामीणों ने भी सशर्त दाह संस्कार की अनुमति दी। जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला ग्राम पंचायत नवागांव का है, जहां धर्मातरित महिला महेश्वरी साहू की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। साहू परिवार द्वारा ईसाई धर्म अपनाए जाने की बात सामने आने



के बाद ग्रामीणों ने महिला के शव को गांव में दफनाने पर आपर्ति जताई। विवाद के बीच ग्रामीणों और परिवार के बीच बातचीत हुई।

इसके बाद परिवार की ओर से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई गई। इसके बाद ग्रामीणों ने भी सशर्त दाह संस्कार की अनुमति दी। फिलहाल पूरे मामले

को लेकर गांव में तनाव की स्थिति के बीच प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को संभाला गया। धर्मांतरण के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर उठा विवाद अब सहमति के बाद शांत होता नजर आया। हालांकि, पूरे मामले ने इलाके में धर्मांतरण और अंतिम संस्कार की परंपराओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।



प्रधानमंत्री आवास योजना विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव

पक्के घरों से बदल रही गांवों की तस्वीर,
आत्मसम्मान से भर रहा हर परिवार



हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, यह केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का अभियान है। विकसित भारत के निर्माण में आवास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

“हमारी सरकार का लक्ष्य है, कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे। पक्का घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव है।
श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

पक्का घर : सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का आधार

छत्तीसगढ़ में आवास योजना का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने आवास निर्माण को केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनकल्याण के व्यापक अभियान का स्वरूप दिया है। गांव-गांव तक पहुंची इस पहल ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का नया अध्याय जोड़ा है।

एक समय था जब प्रदेश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार कच्चे मकानों, झोपड़ियों और अस्थायी आवासों में जीवनयापन करने को मजबूर थे। बरसात में टपकती छतें, गर्मियों में असहनीय तापमान और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन संघर्ष का पर्याय बन चुका था। आज वही परिवार मजबूत पक्के मकानों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन मोड में धरातल पर उतारते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।

आवास से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन

प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल ईट और सीमेंट के ढांचे खड़े नहीं किए हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी है। प्रदेश के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों, आदिवासी बहुल इलाकों और नक्सल प्रभावित अंचलों तक विकास की मुख्यधारा पहुंचाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज हजारों गांवों में नए आवासों के साथ बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, गैस कनेक्शन, सड़क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है।

आवास अब केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सम्मान का आधार बन गया है।



नया घर, नई उम्मीद

सुशासन, तकनीक और पारदर्शिता का मॉडल

छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक और सुशासन को प्राथमिकता दी है।

तकनीक से पारदर्शिता

- डिजिटल मॉनिटरिंग**
हर आवास की प्रगति पर निरंतर नजर
- जियो टैगिंग**
प्रत्येक आवास का भौगोलिक सत्यापन
- सीधा लाभ**
हस्तांतरण लाभ सीधे हितग्राही के खाते में
- जन सहभागिता**
आवास मित्र, पंचायत और स्थानीय हितग्राहियों की सक्रिय भूमिका
- पारदर्शिता और जवाबदेही**
शिकायत निवारण और ऑनलाइन निगरानी

डिजिटल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, ऑनलाइन सत्यापन, हेलपलाइन सेवाएं और तकनीकी निगरानी तंत्र के माध्यम से प्रत्येक आवास की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ी है और लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।

आदिवासी अंचलों में विकास का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ने विकास की नई कहानी लिखी है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार अब पक्के और सुरक्षित घरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विकास की किरण पहुंची है।

इन क्षेत्रों में आवास निर्माण के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का भी विस्तार हुआ है।



रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

26 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति



विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए 33000 आवासों की स्वीकृति



आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के लिए विशेष 15000 आवास



महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी

निर्माण सामग्री आपूर्ति और भवन निर्माण सहयोग से विकास की मुख्यधारा से जुड़ते परिवार और बढ़ती आत्मनिर्भरता।

जब घर बना, तब बदली जिंदगी

बस्तर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, सक्ती, मुंगेली और प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके लिए पक्का मकान कभी एक सपना था आज वही सपना साकार हो चुका है। पक्का घर मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई हैं और परिवार में आत्मविश्वास बढ़ा है।



महिलाओं के नाम पर बढ़ रहा स्वामित्व और सम्मान

योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त स्वामित्व में स्वीकृत किए गए हैं। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण मजबूत हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही, बल्कि परिवार की आर्थिक योजनाओं, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जल संरक्षण के साथ हरित विकास

छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास निर्माण को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा है। ‘मोर गांव-मोर पानी’ जैसे अभियानों के माध्यम से नए आवासों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल भविष्य के लिए जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में बढ़ा कदम है।



डिजिटल छत्तीसगढ़, मजबूत कदम

ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, डिजिटल सत्यापन और तकनीकी निगरानी ने योजना की विश्वसनीयता बढ़ाई है। डिजिटल माध्यमों से शिकायत निवारण और प्रगति समीक्षा की व्यवस्था ने सुशासन की नई मिसाल प्रस्तुत की है।



रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान की है। आवास निर्माण कार्यों से हजारों स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रों, निर्माण सामग्री विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। कई जिलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह निर्माण सामग्री आपूर्ति, भवन निर्माण सहयोग और अन्य सेवाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

संवाद-48873/2



विकसित भारत - विकसित छत्तीसगढ़ की ओर

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से
समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर



हर घर तक स्वच्छ पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएम साय



राजेश कुमार टोप्पो ने बैठक में बताया कि जल संचय जन भागीदारी अभियान में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के साथ उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रयास तभी दीर्घकालिक परिणाम देंगे, जब शासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। जनभागीदारी की इसी शक्ति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थायी रूप से स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत सभी जिलों के नोटिफाइड नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अभियान की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए तथा जहां भी कमियां सामने आएँ, उन्हें तत्काल दूर किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान की जिलेवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में काम किया जाए।

जनभागीदारी से मजबूत होगा जल संरक्षण अभियान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल संरक्षण को केवल शासकीय कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाना चाहिए। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के अनेक जिलों ने जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब सभी जिलों को अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर बेहतर परिणाम के लिए प्रयास करना होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभियान की जिलेवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कोरिया, धमतरी राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में जल संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के अनुभव और कार्यप्रणाली का लाभ अन्य जिलों को भी मिलना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के प्रयासों को समान गति मिल सके। जल संसाधन विभाग के सचिव श्री

मुख्यमंत्री ने किया स्वदेशी मेला के पोस्टर एवं ब्रोशर का विमोचन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई दुर्ग, राजनांदगांव एवं अंबिकापुर में आयोजित होने वाले इस वर्ष के स्वदेशी मेला के आधिकारिक ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच प्रांत के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं पूर्व मंत्री एवं विधायक अमर अग्रवाल सहित अमरजीत सिंह छाबड़ा, युगबोध अग्रवाल, अमर बंसल, सुब्रत चाकी, जसप्रीत सलूजा, श्रीमती मनीषा सिंह, डॉ. सुशील श्रीवास्तव, डॉ. प्रफुल्ल शर्मा, गुलशन ऋषि, श्रीमती अरुणा दीक्षित, विष्णु साव, विनोद डड्डा, योगेश बागड़ी, दिनेश पाटील, अजय भसीन, शंकर सचदेव विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मेला के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मेलों से स्थानीय कारीगरों, स्व-सहायता समूहों और स्वदेशी उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले इन मेलों की तिथियां एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ परिवहन मंत्री कश्यप की सार्थक चर्चा

यात्री किराए के विषय का शीघ्र होगा समाधान

रायपुर। परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बस संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में यात्री किराए के पुनर्निर्धारण, स्लीपर बसों के टैक्स, बसों की समय-सारिणी, ऑनलाइन परमिट, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, फिटनेस प्रमाण-पत्र और महिला यात्रियों की सुरक्षा सहित परिवहन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई।



परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई प्रत्येक मांग और व्यावहारिक समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बस संचालकों की समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाए और यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ तथा सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यात्री किराए के विषय का शीघ्र होगा समाधान

बैठक में फेडरेशन ने साधारण यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत तथा डीलसस बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग रखी। इसके साथ ही 11 मार्च 2025 को जारी संशोधित अधिपूचना को निरस्त करने का विषय भी मंत्री के समक्ष रखा गया।

परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने प्रतिनिधियों को आश्वासित किया कि यात्री किराए से जुड़े विषय का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी करते हुए इस विषय पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

स्लीपर बसों के टैक्स पर किया जा रहा विचार

फेडरेशन ने स्लीपर बसों में एक स्लीपर के बदले दो सीटों का टैक्स लेने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर एक स्लीपर पर एक सीट के बराबर टैक्स

निर्धारित करने की मांग रखी। बस संचालकों ने इस व्यवस्था से होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी भी मंत्री को दी।

समय-सारिणी व्यवस्थित करने के निर्देश

स्टेज कैरिज बसों के बीच समय-अंतराल निर्धारित करने के विषय पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। फेडरेशन ने मुख्य मार्गों पर बसों के बीच 10 मिनट तथा ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतर निर्धारित करने का सुझाव दिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों की समय-सारिणी ऐसी होनी चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की आगामी व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बुधवार 9 सितम्बर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित संघ मुख्यालय में बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्राधिकृत अधिकारी एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री शशिकांत द्विवेदी ने की। बैठक में संघ के वित्तीय, प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक अनुमोदन एवं निर्णय लिए गए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तार

अनुमोदित किया गया। बैठक में इसके अतिरिक्त वेतन मैट्रिक्स में संशोधन, विभिन्न वाहनों की बिक्री, लॉबित परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति तथा उच्च न्यायालय में संघ के पक्ष-प्रतिरक्षण हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति सहित अन्य प्रशासनिक एवं संस्थागत विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान प्राधिकृत अधिकारी एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री शशिकांत द्विवेदी ने संघ की उपलब्धता एवं अन्य व्यावसायिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्णयों को



चक्रधर समारोह में बिखेरेंगी संस्कृति के रंग

कविता कृष्णमूर्ति, अनुज शर्मा, भारती बंधु और इंडियन आइडल फेम कलाकारों समेत देश-प्रदेश की नामचीन प्रतिभाएं देंगी प्रस्तुति

रायपुर। महाराजा चक्रधर सिंह की कला-साधना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित 41वें अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह-2026 में इस बार कला और संस्कृति के विविध रंग एक साथ देखने को मिलेंगे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 14 से 23 सितम्बर तक आयोजित होने वाले इस दस दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ में स्थानीय प्रतिभाओं से लेकर देश-प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। प्रतिदिन शाम 6 बजे से शुरू होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में शास्त्रीय नृत्य, छत्तीसगढ़ी लोककला, पंडवानी, लोकसंगीत, कबीर भजन, गजल और वाद्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति की समृद्ध परंपरा जीवंत होगी।

संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं जनसहयोग से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में पद्मश्री सम्मानित



कलाकारों के साथ इंडियन आइडल फेम कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। समारोह की खासियत यह होगी कि हर शाम कला की एक अलग विधा और अलग रंग दर्शकों के सामने आएगा। दस दिनों तक रायगढ़ का रामलीला मैदान सुर, ताल, नृत्य और लोक परंपराओं के अनूठे संगम का साक्षी बनेगा।

समारोह का शुभारंभ 14 सितम्बर को श्री वेदमणि सिंह ठाकुर के शिष्यों द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति से होगा। इसके बाद पद्मश्री सम्मानित श्री अनुज शर्मा लोक कला एवं संगीत की

प्रस्तुति देंगे। वहीं पद्मश्री सम्मानित डॉ. उषा बारले अपनी पंडवानी प्रस्तुति से पहली सांस्कृतिक संध्या को यादगार बनाएंगी। लोकधुनों, लोकगाथाओं और पंडवानी की सशक्त परंपरा से समारोह का आगाज होगा।

15 सितम्बर की शाम में निशित गंगानी का तबला वादन, टी. लक्ष्मी रेड्डी की कुचिपुड़ी प्रस्तुति, स्टार्क सोसाइटी बाइमेर की राजस्थानी फोक प्रस्तुति और तरुणा साहू एवं समूह की पंडवानी प्रस्तुति होगी। इसके साथ माधवरस बैंड द्वारा भजन गायन की

प्रस्तुति सांस्कृतिक संध्या को भक्तिरस से सराबोर करेगी।

16 सितम्बर को छत्तीसगढ़ की विविधता मंच पर दिखाई देगी। मौमाला नायक कथक की प्रस्तुति देंगी। भूपेन्द्र साहू एवं समूह छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य प्रस्तुत करेंगे। डॉ. यास्मीन सिंह एवं समूह तथा सुश्री विभूति शर्मा द्वारा कथक की प्रस्तुतियां होंगी, जबकि पायल साहू एवं समूह लोककला के रंग बिखेरेंगे।

17 सितम्बर की शाम लोककला एवं संगीत के साथ शास्त्रीय नृत्य की अनेक विधाओं का संगम देखने को मिलेगा। बादल-बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट्स एवं लिटरेचर द्वारा लोक कला एवं संगीत की प्रस्तुति होगी। मधुमिता रॉय मिश्रा कथक और

जान्हवी बेहरा ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। शिवरंजनी हरीश एवं कलार्पणा नृत्य समूह पद्म भूषण शोभना के शिष्यगण भरतनाट्यम की

प्रस्तुति देंगे। शिव शक्ति कला संस्थान द्वारा कथक की प्रस्तुति भी होगी।

18 सितम्बर को डॉ. मंजू इलंगबम मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। पद्मश्री सम्मानित श्री भारती बंधु कबीर भजनों से आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करेंगे। श्वेता नायक एवं समूह कुचिपुड़ी तथा श्री अनुराग शर्मा लोकसंगीत की प्रस्तुति देंगे।

19 सितम्बर कला और साहित्य के प्रेमियों के लिए खास होगी। गौरी शंकर दाश और रीला होता ओडिसी नृत्य की प्रस्तुतियां देंगी। वहीं पद्मश्री सम्मानित श्री सुरेन्द्र शर्मा एवं अन्य कलाकार काव्य संध्या के माध्यम से हास्य और साहित्य का रंग भरेंगे। नृत्य और काव्य का यह संगम समारोह की शाम को विशिष्ट बनाएगा।

20 सितम्बर को श्री बी. साहू एवं समूह गोटीपुआ नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इंडियन आइडल फेम अमित साना अपनी गायन प्रस्तुति से संगीत प्रेमियों का मनोरंजन करेंगे।

विकास कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर विशेष जोर

रायपु। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज बीजापुर में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन विभागों के स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं का लाभ नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बीजापुर जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़कों, पुलों, शासकीय भवनों तथा अधोसंरचना विकास के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब पर रोक लगाने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों की



वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री द्वारा फुंडरी में निर्माणाधीन पुल की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। श्री साव ने शेष कार्यों को शीघ्र पूरा कर पुल को आवागमन के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं बेदरे में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल के संबंध में अधिकारियों ने रिटेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने तथा वर्क ऑर्डर जारी किए जाने की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने और निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने बासागुड़ा में तालपेरु नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल

सहित जिले के अन्य पुल-पुलियों की प्रगति की भी समीक्षा की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 'हर घर जल' योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार तक नियमित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं की सतत निगरानी, अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की।

किरेन रिजीजू से मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने की सौजन्य भेंट



रायपुर। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री,भारत सरकार किरेन रिजीजू से नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमेन (राज्य मंत्री दर्जा) मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने सौजन्य मुलाकात की। इस भेंट के दौरान श्री बेग ने केन्द्रीय को हज 2026 के सफलता पूर्वक संपादन की बधाई देते हुए इस वर्ष हज के दौरान हाजियों को उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने केन्द्रीय से राज्य के हज यात्रियों की व्यवस्थाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी किए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन हज आवेदन हेतु हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज कमेटी के कार्यालय में पृथक से एक काउंटर की व्यवस्था की गई, जहां से बड़ी संख्या में आवेदन किए गए। राज्य के लोगों को हज संबंधित अधिक से अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से विगत दिनों छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है।

राज्य सहकारी विपणन संघ की बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की आगामी व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बुधवार 9 सितम्बर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित संघ मुख्यालय में बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्राधिकृत अधिकारी एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री शशिकांत द्विवेदी ने की। बैठक में संघ के वित्तीय, प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक अनुमोदन एवं निर्णय लिए गए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तार

अनुमोदित किया गया। बैठक में इसके अतिरिक्त वेतन मैट्रिक्स में संशोधन, विभिन्न वाहनों की बिक्री, लॉबित परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति तथा उच्च न्यायालय में संघ के पक्ष-प्रतिरक्षण हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति सहित अन्य प्रशासनिक एवं संस्थागत विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान प्राधिकृत अधिकारी एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री शशिकांत द्विवेदी ने संघ की उपलब्धता एवं अन्य व्यावसायिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्णयों को